

बंगाल में तहस-नहस हो गई नारी प्रतिष्ठा की संस्कृति

शर्मिष्ठा की अर्जी पर हाईकोर्ट ने की फूहड़ टिप्पणी

जमानत नहीं दी तो क्या आसमान टूट पड़ेगा!

कलकत्ता, 03 जून (एजेंसियां)। बंगाल की संस्कृति मां-बेटियों को सम्मान देने और उनकी पूजा करने के लिए विख्यात रही है। उस बंगाल में न्यायालय तक का चारित्रिक स्खलन इस स्तर पर पहुंच गया है कि एक मासूम लड़की को जेल में भी बलात्कार करने और सिर तन से जुदा करने जैसी गंदी धमकियां दी जा रही हैं। जेल में उसे अशुद्ध पानी दिया जा रहा है और उसे जरूरी दवाइयां भी नहीं दी जा रही हैं। लेकिन अदालत कहती है कि जमानत नहीं देने से कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा। चरित्र और नैतिकता का आसमान टूट ही चुका है, यह देखने की नैतिक शक्ति न पश्चिम बंगाल सरकार के पास बची है न सत्ता-चाटुकार अदालतों के पास। जिस व्यक्ति की

शिकायत पर कलकत्ता की अदालत ने एक छोटी बच्ची का मान-मर्दन किया, वह शख्स देवी कामाख्या समेत अन्य हिंदू देवी-देवताओं पर गंदी टिप्पणी करने के मामले में कुख्यात है। लेकिन उस पर कार्रवाई करने में ममता सरकार को कोई रुचि नहीं है और अदालतों को उस पर संज्ञान लेने की फुर्सत है। उसे तो पहलगाम में हिंदुओं को चुन-चुन कर मारे जाने की निंदा करने वाले संजीदा हिंदुओं को निपटाने की जल्दी है।

कलकत्ता हाईकोर्ट ने 22 वर्षीय छात्रा शर्मिष्ठा पनोली को जमानत देने से यह कहते हुए इंकार कर दिया कि शर्मिष्ठा को जमानत नहीं देने से कोई आसमान नहीं गिर पड़ेगा। टिप्पणी का यह स्तर कलकत्ता हाईकोर्ट का है। इससे आप निचली



शर्मिष्ठा को जेल में मिल रही धमकियां एनएचआरसी ने की पुष्टि

अदालतों का स्तर समझ सकते हैं। इससे पहले, कलकत्ता स्थित अलीपुर कोर्ट ने 31 मई को शर्मिष्ठा के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया था और उसे 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया था।

जेल में शर्मिष्ठा पनोली को मिल रही गंदी धमकियां और गंदा पानी की शिकायतों को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान में लिया है। आयोग ने बंगाल सरकार से त्वरित रूप से जवाब मांगा है और शर्मिष्ठा की हिफाजत का पूरा ध्यान रखने की सख्त हिदायत दी है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने कहा, शर्मिष्ठा को गिरफ्तार होने के बाद से बलात्कार और जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, जिसके बाद आयोग ने यह कदम उठाया है।

मानवाधिकार आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी से शर्मिष्ठा की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है। साथ ही, हरियाणा सरकार से भी पूछा है कि क्या गिरफ्तारी के दौरान सभी नियम-कानूनों का पालन किया गया था? उल्लेखनीय है कि कलकत्ता पुलिस ने पिछले दिनों हरियाणा के गुरुग्राम आकर शर्मिष्ठा को गिरफ्तार कर लिया और गुरुग्राम प्रशासन मुंह ताकता रहा। शर्मिष्ठा की तरफ से अलीपुर जिला अदालत में दाखिल याचिका में कहा गया था कि उन्हें जेल के अंदर अन्य कैदियों से कई तरह की धमकियां मिल रही हैं। शर्मिष्ठा ने कहा था कि उन्हें अपनी सुरक्षा का डर सता रहा है। शर्मिष्ठा को अलीपुर के महिला सुधार गृह में रखा गया है। ▶10पर

भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने विश्व में बढ़ाया देश का मान

युद्ध-विराम में कोई मध्यस्थ नहीं था : शशि थरूर

ब्रासीलिया, 03 जून (एजेंसियां)।

ऑपरेशन सिंदूर के बाद विश्व के देशों का दौरा कर रहे सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की एक टीम के नेता शशि थरूर ने अमेरिका समेत कई देशों के समक्ष यह स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध विराम में किसी भी तीसरे पक्ष की भूमिका नहीं थी। शशि थरूर ने साफ-साफ कहा कि युद्ध विराम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप की कोई भूमिका नहीं थी। युद्ध विराम का प्रस्ताव पाकिस्तान की तरफ से आया था और भारत सरकार ने इस पर विचार करने के बाद सम्यक निर्णय लिया। थरूर ने कहा, भारत अपने मामले में किसी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेगा। शशि थरूर ने कहा, हमने 7 मई को शुरू से ही कहा कि हम संघर्ष को लंबा खींचने के इच्छुक नहीं हैं। यह किसी तरह के युद्ध की शुरुआत नहीं है। यह सिर्फ आतंकवादियों के खिलाफ प्रतिशोध है, बस। अगर पाकिस्तान ने प्रतिक्रिया नहीं की होती, तो हम भी प्रतिक्रिया नहीं करते।

ऑपरेशन सिंदूर पर सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भारत-पाकिस्तान संघर्ष विराम में तीसरे पक्ष की मध्यस्थता से इंकार किया और कहा कि संघर्ष विराम के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच सीधी बातचीत हुई। थरूर के नेतृत्व वाला सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल फिलहाल ब्राजील में है और ब्राजील से अमेरिका के लिए रवाना होगा। गौरतलब है कि अमेरिकी

पाकिस्तान का प्रस्ताव था, भारत ने निर्णय लिया
ऑपरेशन सिंदूर को ब्राजील का भी समर्थन मिला

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार-बार दावा कर रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम के लिए उन्होंने मध्यस्थता की। इसे शशि थरूर ने साफ-साफ नकार दिया है। ब्राजील में शशि थरूर ने कहा, हम अमेरिकी राष्ट्रपति पद का बहुत सम्मान करते हैं और हम उसी सम्मान को ध्यान में रखते हुए बात करेंगे, लेकिन मोटे तौर पर कहें तो हमारी समझ थोड़ी अलग है। हमें रोकने के लिए किसी को मनाने की जरूरत नहीं थी। हमने पहले ही रुकने के लिए कह दिया था। अगर अमेरिकी राष्ट्रपति या उनके वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किसी को मनाने की

जरूरत थी, तो वह पाकिस्तानियों को मनाने की थी। उन्हें मनाना पड़ता। हमें मनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम युद्ध नहीं चाहते। हम विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। यही मूल संदेश है।

डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि भारत-पाकिस्तान के बीच उन्होंने ही मध्यस्थता कराई। ट्रंप ने ही सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में सबसे पहले भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम की जानकारी दी थी। हालांकि भारत ने ट्रंप ने दावे को उस समय भी खारिज कर दिया था। भारत ने बताया था कि पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन (डीजीएमओ) ने भारतीय समकक्ष को फोन करके संघर्ष विराम की अपील की थी। जिसके बाद संघर्ष विराम हुआ।

पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर को ब्राजील का समर्थन मिला है। ब्राजील ने भारत सरकार के द्वारा आतंकी गतिविधियों की रोकथाम के लिए ऑपरेशन सिंदूर के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया और पाकिस्तान के द्वारा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की कड़ी भर्त्सना की। प्रतिनिधिमंडल में शामिल भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने यह अधिकारिक जानकारी दी। तेजस्वी सूर्या शशि थरूर की अगुवाई वाले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य हैं। सूर्या ने कहा, ब्राजीलिया में हमने ब्राजील की संसद के अध्यक्ष, कार्यवाहक विदेश मंत्री और भारत-ब्राजील मैत्री समूह के ▶10पर

पाकिस्तान छोड़ कर आए लोगों को हक देने की सुध आई

अब तक शरणार्थी थे, अब मिलेगा मालिकाना हक

लखनऊ, 03 जून (एजेंसियां)।

उत्तराखंड की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी उन पाकिस्तानी शरणार्थियों को जमीन का मालिकाना हक दिया जाएगा जो देश विभाजन के समय पाकिस्तान से भारत आ गए थे। आंजनेय कमेटी की रिपोर्ट पर योगी सरकार शीघ्र ही औपचारिक निर्णय लेगी। इस पर योगी सरकार बाकायदा कानून बनाने पर विचार कर रही है।

मुरादाबाद के मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। वर्तमान में करीब 20 हजार शरणार्थी परिवार 50 हजार एकड़ भूमि पर रह रहे हैं, लेकिन उन्हें जमीन का मालिकाना हक आज तक नहीं मिला। 1947 में भारत-पाक विभाजन के समय पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को लखीमपुर खीरी, रामपुर, बिजनौर और पीलीभीत में बसाया गया था। इन्हें जीविकोपार्जन के लिए जमीन भी दी गई थी। इनमें से अधिकतर हिंदू और सिख शरणार्थी थे। लेकिन, इनमें से तमाम परिवारों को संक्रमणीय भूमिधर अधिकार नहीं मिला। यानि, इन परिवारों के वारिस अपनी जमीन पर बैंक से फसली ऋण के अलावा कोई और ऋण नहीं ले सकते। उन्हें जमीन बेचने का भी अधिकार नहीं है। रामपुर में शरणार्थियों के 23 गांव हैं। बिजनौर में ये शरणार्थी अलग-अलग 18 गांव में बसे हैं। लखीमपुर खीरी और पीलीभीत में अलग-अलग गांवों में या

यूपी में रह रहे हैं 20 हजार शरणार्थी परिवार
आंजनेय कमेटी ने की ऐतिहासिक सिफारिश

जंगलों के किनारे ये लोग बसाए गए। आंजनेय कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ शरणार्थी परिवारों को तब गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट (सरकारी भूमि अनुदान अधिनियम) के तहत जमीन दी गई थी। ग्राम सभा और विभिन्न विभागों की स्वामित्व वाली जमीन पर भी बसाया गया। वर्तमान में गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट समाप्त हो चुका है। इन शरणार्थी परिवारों को दी गई जमीन पर पूर्ण स्वामित्व यानी संक्रमणीय भूमिधर अधिकार देने के लिए अलग से कानून बनाने की आवश्यकता होगी, ताकि इन मामलों में मौजूदा नियम शिथिल किए जा सकें। उत्तराखंड के कई जिलों में स्वामित्व देने का काम जमीन का कुछ प्रतिशत मूल्य लेकर किया जा चुका है। उत्तराखंड की तरह ही यहां भी कुछ मूल्य लेकर या निशुल्क संक्रमणीय भूमिधर अधिकार दिया जा सकता है। अलबत्ता, कुछ शरणार्थी परिवार आरक्षित श्रेणी की वन भूमि, ▶10पर



संक्रमणीय भूमिधर अधिकार दिया जा सकता है। अलबत्ता, कुछ शरणार्थी परिवार आरक्षित श्रेणी की वन भूमि, चरागाह और तालाब पर भी बसे हैं।

आंजनेय कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि इन्हें अन्यत्र जमीन देने या फिर उसी जमीन पर स्वामित्व अधिकार देने के लिए कानून में बदलाव करने पर विचार करना होगा। वन भूमि पर अधिकार देने के लिए केंद्र सरकार के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट की अनुमति भी लेनी होगी। वहीं, नियमानुसार ग्राम सभा की भूमि उसी गांव के मूल निवासियों को दी जा सकती है। इसी तरह से विभागों की भूमि देने का अधिकार भी संबंधित विभागों को ही है। इस मामले में अब आगे विचार करने के लिए कैबिनेट की उप समिति बनाई जा सकती है। अंतिम निर्णय सरकार को ही लेना है।

कमेटी से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि शरणार्थी परिवारों को दी गई जमीन पर पूर्ण स्वामित्व यानि संक्रमणीय भूमिधर अधिकार देने के लिए अलग से कानून बनाने की आवश्यकता होगी, ताकि इन मामलों में मौजूदा नियम शिथिल किए जा सकें। उत्तराखंड के कई जिलों में स्वामित्व देने का काम जमीन का कुछ प्रतिशत मूल्य लेकर किया जा चुका है। उत्तराखंड की तरह ही यहां भी कुछ मूल्य लेकर या निशुल्क संक्रमणीय भूमिधर अधिकार दिया जा सकता है। अलबत्ता, कुछ शरणार्थी परिवार आरक्षित श्रेणी की वन भूमि, ▶10पर

एलन मस्क के पिता ने की सनातन धर्म की सराहना

दुनिया शिव की आराधना करे, सब ठीक हो जाएगा



नई दिल्ली, 03 जून (एजेंसियां)।

अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क के पिता एरोल मस्क ने सनातन धर्म की सराहना करते हुए कहा कि दुनिया भगवान शिव का अनुसरण करना शुरू कर दे तो सब ठीक हो जाएगा। एरोल ने कहा, मैं सनातन धर्म का कोई विशेषज्ञ तो नहीं हूं, लेकिन इससे प्रभावित जरूर हूं। यह इतना पुराना धर्म है कि ये मुझे हैरान कर देता है। यह हमें बताता है कि हकीकत में हम कितना कम जानते हैं। एलन मस्क के पिता एरोल मस्क ने अपने भारत दौरे पर अयोध्या में राम मंदिर का भी दर्शन किया। राम मंदिर का दर्शन करने के बाद एरोल मस्क ने कहा, मैं सनातन की प्राचीनता से चकित हूं। दुनिया को शिव की आराधना करनी चाहिए। इससे सब ठीक हो जाएगा। सीनियर मस्क ने भारत को विश्व शक्ति कहा और ▶10पर

पाक के ब्रह्मपुत्र-प्रलाप का असम के सीएम ने दिया कशरा जवाब

परमाणु ब्लैकमेल नहीं चला, ब्रह्मपुत्र ब्लैकमेल भी नहीं चलेगा

नई दिल्ली, 03 जून (एजेंसियां)।

सिंधु नदी जल समझौता स्थगित होने से पाकिस्तान एक बार फिर चीन के कंधे पर सवार होकर भारत के खिलाफ दुष्-प्रचार कर रहा है। पाकिस्तानी प्रोपेगंडा को लेकर फैल रही खबरों पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने मोर्चा संभाला है। उन्होंने पाकिस्तान की झूठी कहानी की हवा निकाल दी है।

मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि भारत ने जबसे सिंधु जल संधि स्थगित कर दी, तबसे पाकिस्तान एक नई घबराहट फैलाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान कह रहा है, अगर चीन ब्रह्मपुत्र का पानी रोक दे तो? इस पर मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि इस झूठी कल्पना को डर से नहीं, बल्कि तथ्यों और राष्ट्रीय स्पष्टता से देखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अगर चीन



पाकिस्तान को यथार्थ का ज्ञान नहीं केवल बकवास पर भरोसा

ब्रह्मपुत्र का पानी रोक दे तो वह भारत के लिए मददगार साबित होगा, क्योंकि हर

वर्ष असम में आने वाली भीषण बाढ़ से लाखों लोग विस्थापित होते हैं और भारी

तबाही होती है। ब्रह्मपुत्र एक ऐसा नद है जो भारत में बढ़ता है, घटता नहीं है। चीन ब्रह्मपुत्र के कुल जल प्रवाह में केवल 30-35 प्रतिशत योगदान देता है। वह भी ज्यादातर हिमनदों के पिघलने और सीमित वर्षा से। शेष 65-70 प्रतिशत जल भारत के भीतर ही उत्पन्न होता है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश, असम, नगालैंड और मेघालय में मूसलाधार मानसूनी वर्षा, प्रमुख सहायक नदियां जैसे सुबनसिरी, लोहित, कामेंग, मानस, धनसिरी, जिया-भाराली, कोपिली के जरिए ब्रह्मपुत्र में जाता है। वहीं, मेघालय की खासी, गाब्रो और जयंतिया पहाड़ियों से जल कृष्णाई, दिगारू, कुलसी आदि सहायक नदियों के जरिए ब्रह्मपुत्र में जाता है। भारत-चीन सीमा (तृतिंग) पर प्रवाह 2,000-3,000 घन मीटर/सेकंड है। ▶10पर

कार्रवाई में दखल देने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार

कुख्यात बाटला हाउस पर चलेगा बुलडोजर



नई दिल्ली, 03 जून (एजेंसियां)।

दिल्ली के जामिया नगर स्थित बाटला हाउस में 40 सम्पत्ति मालिकों के अवैध कब्जे को ध्वस्त करने के लिए राज्य सरकार की ओर से जारी किए गए नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरह से हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है। साथ ही अदालत ने इन याचिकाकर्ताओं को इस मामले से जुड़े संबंधित अधिकारियों से संपर्क करने का सुझाव दिया है। इस तरह बाटला हाउस पर कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है।

जस्टिस संजय करोल और सतीश वर्मा की पीठ अवकाश पीठ ने इस मामले की आगली सुनवाई को एक माह के बाद जुलाई तक के लिए आगे बढ़ा दिया है। याचिकाकर्ताओं ने दिल्ली विकास प्राधिकरण के नोटिस को गलत करार देते हुए आरोप लगाया था कि उन्हें मामले ▶10पर



सांसद चौटा ने आतंकवाद के खिलाफ उच्च स्तरीय मिशन में भारत का प्रतिनिधित्व किया



5 देशों का दौरा संपन्न

बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो। दक्षिण कन्नड़ से सांसद कैप्टन बृजेश चौटा ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ देश के दृढ़ रुख को उजागर करने के लिए पांच देशों के दौरे पर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले एक उच्च स्तरीय सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल के हिस्से के रूप में एक महत्वपूर्ण राजनयिक मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया है। यह मिशन ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के विस्तारित वैश्विक आउटरीच का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य आतंकवाद के प्रति अपनी शून्य-सहिष्णुता की नीति को मजबूत

करना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना था। कैप्टन बृजेश चौटा ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, इस अभियान का उद्देश्य आतंकवाद के खिलाफ भारत की एकजुट आवाज को वैश्विक समुदाय तक पहुंचाना और आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले राज्य के रूप में पाकिस्तान के मुखांश को उजागर करना था। उन्होंने कहा इस तरह के महत्वपूर्ण मंच पर न केवल भारत बल्कि अपने गृह क्षेत्र दक्षिण कन्नड़ का प्रतिनिधित्व करना बहुत गर्व की बात थी। राजनयिकों, विदेशी सरकारी अधिकारियों और यूरोप भर के विचारकों के साथ जुड़ना एक दुर्लभ और समृद्ध प्रशासनिक अनुभव प्रदान करता है। उन्होंने

कहा यह विदेशी मिशन बेहद यादगार और सार्थक रहा है। मैं इस प्रतिष्ठित प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बनने का अवसर देने के लिए केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। स्पेन में प्रतिनिधिमंडल का अंतिम पड़ाव मैड्रिड में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ शुरू हुआ, जो भारत के शांतिपूर्ण लेकिन दृढ़ दृष्टिकोण का प्रतीक है। टीम ने भारतीय प्रवासियों के साथ बातचीत की, जहां 26/11 मुंबई आतंकवादी हमलों में जीवित बचे स्पेनिश व्यवसायी आर्टुरो फर्नांडीज अल्वारेज ने एकजुटता दिखाई और पाकिस्तान समर्थित

आतंकवाद की निंदा करने के आह्वान में शामिल हुए। अंतिम दिन, यूरोप परिषद की संसदीय सभा के उपाध्यक्ष एंटोनियो गुटियरेज लिमोन्स और स्पेनिश सीनेट की विदेश मामलों की समिति के साथ बैठक हुई। प्रतिनिधिमंडल ने स्पेनिश सरकार के सदस्यों, नागरिक समाज के प्रतिनिधियों और आतंकवाद के पीड़ितों के संघ के साथ भी बातचीत की, जो 4,800 से अधिक आतंकवाद पीड़ितों का समर्थन करता है। स्पेन से पहले, प्रतिनिधिमंडल ने लातविया का दौरा किया, जहाँ उन्होंने सेइमा की विदेश मामलों की समिति की अध्यक्ष इनारा मुर्निंस और भारत-लातविया

मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर ने हिडकल बांध से धारवाड़ तक पानी मोड़ने में शामिल होने से किया इनकार

बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो।

कर्नाटक की महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर ने इस बात से इनकार किया है कि बेलगावी के हिडकल से घाटप्रभा नदी के पानी को धारवाड़ के औद्योगिक क्षेत्र में मोड़ने के पीछे उनका हाथ था। उन्होंने बेलगावी में संवाददाताओं से कहा मेरा उस योजना से कोई लेना-देना नहीं है। वास्तव में, मुझे यह भी नहीं पता था कि हिडकल से धारवाड़ तक पानी मोड़ा जा रहा है। इसके लिए मुझे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना है। उन्होंने इन आरोपों को निराधार बताया कि उन्होंने धारवाड़ में अपने बेटे (मृणाल हेब्बालकर) की चीनी फैक्ट्री की जरूरतों को पूरा करने के लिए हिडकल से धारवाड़ तक पानी मोड़ने के लिए संबंधित मंत्रियों को प्रभावित किया था। उन्होंने कहा मेरे परिवार की गन्ना फैक्ट्री में पर्याप्त पानी है। हमारे पास पास में एक नाला बहता है। मैंने आस-पास 15 बोरवेल खोदे हैं। प्रत्येक बोरवेल से 3-5 इंच पानी निकलता है। हमें बाहरी पानी की आपूर्ति की आवश्यकता नहीं है। यह पूछे जाने पर कि वह हिडकल से धारवाड़ तक पानी के डायवर्जन का विरोध क्यों नहीं कर रही हैं,



उन्होंने दावा किया कि इस मुद्दे पर कोई राय रखने के लिए उन्हें योजना के बारे में उचित जानकारी नहीं है। हालांकि, मैं यह स्पष्ट कर दूँ कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी जो बेलगावी जिले के हितों के लिए हानिकारक हो। पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक रमेश जारकीहोली ने अथानी में संवाददाताओं से कहा कि वह हिडकल से धारवाड़ तक पानी के डायवर्जन का कड़ा विरोध करेंगे। उन्होंने कहा उद्योग मंत्री एम.बी. पाटिल ने कहा है कि वे उद्योगों को पानी मुहैया करा रहे हैं क्योंकि औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। मेरे पास उनसे एक बहुत ही सरल

सवाल है, बेलगावी में उद्योगों को सुविधा क्यों नहीं दी जा रही है, जहां पानी है? अगर नहीं, तो धारवाड़ में उद्योगों से स्थानीय जल स्रोतों का उपयोग करने के लिए क्यों नहीं कहा जा रहा है? वहां पर्याप्त पानी है। पूर्व सिंचाई मंत्री ने कहा कि वे मुख्यमंत्री से संपर्क करेंगे और उन्हें यह विचार छोड़ने के लिए मनाएंगे। जारकीहोली ने कहा मेरे पास यह दिखाने के लिए विश्वसनीय जानकारी है कि धारवाड़ के पास 60 टीएमसीएफटी से अधिक पानी उपलब्ध है। इसका उपयोग उद्योगों के लिए किया जाना चाहिए, न कि हिडकल बांध के पानी का, जो कृषि के लिए है।

रहमान हत्याकांड मामले

आरोपियों को घटनास्थल पर पूछताछ के लिए 4 स्थानों पर ले जाया गया

बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो। कुरियाल गांव के इरा कोडी में 27 मई की शाम को हुई पिकअप वाहन चालक अब्दुल रहमान की हत्या के सिलसिले में पुलिस ने दो मुख्य आरोपियों को सोमवार की शाम को बेल्टांगडी लाया और चार स्थानों पर घटनास्थल पर जांच की। पुलिस ने मामले के सिलसिले में पांच लोगों को गिरफ्तार कर हिरासत में ले लिया है और आरोपियों के विभिन्न स्थानों पर घटनास्थल पर जांच शुरू कर दी है। बंटवाल तालुक के कुरियाल गांव के मुंडारा कोडी के दीपक (21) और उसी तालुक के तेनकाबेल्लूर गांव के सुमित आचार्य (27) को कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच चार स्थानों पर



महाजर (मोके पर जांच) के लिए लाया गया। सूत्रों के अनुसार, अब्दुल रहमान की कथित हत्या के बाद, दो मुख्य आरोपी दीपक और सुमित आचार्य बाइक पर सवार होकर बेल्टांगडी की ओर भाग गए थे। बताया जाता है कि रास्ते में उन्होंने गुरुवयनकेरे की एक दुकान से नए रेनकोट खरीदे,

संथेकट्टे की एक मोबाइल दुकान से सिम कार्ड खरीदा और बाद में सिम को तीन-रोड जंक्शन के पास एक नाले में फेंक दिया। कथित तौर पर, उन्होंने चिक्कमगलूरु की ओर भागने से पहले कलमाने गांव में निंदाल नदी में अपने मोबाइल फोन फेंक दिए।

पर्यावरण कार्यकर्ताओं को 'गोवा सरकार के एजेंट' कहने पर भाजपा सांसद से माफी की मांग

बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो।

कर्नाटक में महादशी बेसिन परियोजनाओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने भाजपा सांसद जगदीश शेडूर से उन्हें 'गोवा सरकार के एजेंट' कहने पर माफी की मांग की है। बेलगावी में कार्यकर्ता सुजीत मुलगांडु ने कहा बेलगावी के सांसद जगदीश शेडूर द्वारा बेलगावी के प्रतिष्ठित पर्यावरणविदों को 'गोवा सरकार के एजेंट' कहना न केवल शर्मनाक है, बल्कि यह सच्चाई, गरिमा और लोगों की लोकतांत्रिक आवाज पर जानबूझकर किया गया हमला है। सांसद को तुरंत सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने संवाददाताओं से कहा



कि जिन कार्यकर्ताओं को शेडूर ने एजेंट कहा है, वे सम्मानित व्यक्तित्व हैं जिन्होंने पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए दशकों तक कड़ी मेहनत की है। दिलीप कामत जो 60 से अधिक वर्षों से निस्वार्थ सक्रियता में शामिल हैं। उन्होंने बाबा आमटे के साथ मिलकर काम किया है और 80,000

एकड़ जंगल को कॉरपोरेट और अन्य लोगों के शोषण से बचाया है। शिवाजीराव कगनीकर, जिन्हें 'उत्तर कर्नाटक के जल पुरुष' के रूप में जाना जाता है, उन्हें राज्योत्सव और देवराज उर्स पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। वे एक गांधीवादी हैं और वंचित वर्गों के लिए न्याय,

वर्षा जल संचयन और वनीकरण के लिए अथक वकालत करते रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल श्रीकृष्ण सरदेशपांडे एक युद्ध नायक हैं, जिन्हें उत्तम युद्ध सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक और राज्योत्सव पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिन्होंने अपने पर्यावरण सक्रियता के साथ भीमगढ़, कोडाचद्री और महादेई संरक्षण क्षेत्रों की नींव रखी। कार्यकर्ताओं में कर्नल रवींद्र सेनी, कैप्टन नितिन धोंड, नायला कोलोहो और शारदा गोपाल भी शामिल हैं। इनमें सामाजिक कार्यकर्ता, वैज्ञानिक, समाज सुधारक, शिक्षक, इस धरती के सभी बेटे और बेटियाँ

शामिल हैं जो पर्यावरण की रक्षा के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। ये बाहरी लोग नहीं हैं। ये बेलगावी की आत्मा हैं, हमारे जंगलों, नदियों और समुदायों के संरक्षक हैं। इन्हें कई सरकारों से पुरस्कार मिल चुके हैं, जिनमें परिसर मित्र पुरस्कार और मुख्यमंत्रियों की प्रशंसा शामिल है। शेडूर को उनका अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है। इन पर्यावरण योद्धाओं ने वह हासिल किया है जिसका राज-नेता केवल वादा करते हैं। उन्होंने वोट या सत्ता मांगे बिना हमारी जमीन की रक्षा की है। शेडूर के हमले में राजनीतिक असुरक्षा की बू आती है और असली मुद्दे से ध्यान हटाने की कोशिश की गई है।

इंस्टाग्राम यूजर पर सांप्रदायिक पोस्ट के लिए मामला दर्ज



बेलगावी/शुभ लाभ ब्यूरो। बेलगावी पुलिस ने एक सोशल मीडिया यूजर के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले संदेश पोस्ट करने के लिए मामला दर्ज किया है। इंस्टाग्राम यूजर को जिले में हाल ही में एक नाबालिग के साथ हुए सामूहिक बलात्कार के बारे में संदेश पोस्ट करने के लिए नोटिस जारी किया गया है। उसने आरोपियों के नाम बताए और मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की। उसने एक खास धर्म के अनुयायियों का अपमान भी किया। पुलिस ने

बीएनएस 192 (दंगा भड़काने के इरादे से जानबूझकर उकसाना) के तहत मामला दर्ज किया है और जांच अधिकारी के सामने पेश होने का नोटिस जारी किया है। पुलिस कमिश्नर बोर्से भूषण गुलाबराव ने लोगों से सोशल मीडिया का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा सभी को कानून और व्यवस्था बनाए रखने और शांति सुनिश्चित करने में सहयोग करना चाहिए। किसी भी कानून का उल्लंघन करने पर सख्ती से निपटा जाएगा।

पुलिस ने तट पर हिंदू कार्यकर्ताओं और नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की

निर्वासित हथियार का इस्तेमाल किया

बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो। सिलसिलेवार हत्याओं के माध्यम से सांप्रदायिक संघर्ष का केंद्र रहे तटीय क्षेत्र में निर्वासन प्रक्रिया ने अब बड़ी चर्चा पैदा कर दी है। सांप्रदायिक और उदारवादी भावना को दबाने के लिए जिला पुलिस रात-रात भर कार्यकर्ताओं और संगठनों के नेताओं के घरों पर छापेमारी कर रही है और जीपीएस लोकेशन ट्रैकर हासिल कर रही है और आधी रात को पुलिस अधिकारी संगठनों के नेताओं और कार्यकर्ताओं को आरोपी की तरह रोक रहे हैं और फोटो खींच रहे हैं। जिला प्रशासन के इस व्यवहार ने हिंदुत्व की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वाले कार्यकर्ताओं में चिंता पैदा कर दी है। दक्षिण कन्नड़ जिले के भाजपा उपाध्यक्ष अरुण पुतिला समेत 36



लोगों को निर्वासित करने का नोटिस दिया गया है। भड़काऊ भाषण देने के आरोप में संघ परिवार के एक प्रमुख नेता प्रभाकर भट समेत कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। कब, किसे और कैसे गिरफ्तार किया जाएगा, इसे लेकर चिंता बनी हुई है। निर्वासन के लिए सूचीबद्ध नामों में अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े संगठनों के नाम भी जोड़े गए हैं। तटीय क्षेत्र राज्य में एक प्रमुख पर्यटन स्थल है,

खासकर दक्षिण कन्नड़ में। यह एक लोकप्रिय निवेश क्षेत्र था। सांप्रदायिक संघर्ष के कारण वहां का माहौल खराब हो गया है और हाल ही में लगातार हत्याएं हुई हैं। सरकार ने तटीय क्षेत्रों में सांप्रदायिक भावनाओं को दबाने और स्थिति को शांत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। सांप्रदायिक हिंसा दमन बल के गठन के लिए पहले ही अधिसूचना जारी की जा चुकी है। पुलिस ने मॉक ड्रिल के जरिए आरोपियों में डर पैदा करने और

जनता का विश्वास बढ़ाने की कोशिश की है। निर्वासन का हथियार इसलिए इस्तेमाल किया गया है क्योंकि कई नेता भड़काऊ भाषणों के जरिए शांति भंग कर रहे हैं। अरुण पुतिला को कलबुर्गी निर्वासित करने के लिए नोटिस जारी किया गया है और सुनवाई 6 जून को तय की गई है। जिला प्रशासन के इस व्यवहार से सार्वजनिक क्षेत्र में आक्रोश फैल गया है। आरोप हैं कि हिंदू कार्यकर्ताओं और नेताओं को निशाना बनाकर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। खासकर अब्दुल रहीम की हत्या के बाद से यह प्रक्रिया तेज हो गई है और कांग्रेस सरकार पर तुष्टिकरण के आरोप लगे हैं। हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह किसी के भी गलत काम को बर्दाश्त नहीं करेगी और कानून को अपने हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी, चाहे वे हिंदू हों या मुसलमान।

मंत्री सतीश जारकीहोली ने मानद डॉक्टरेट की उपाधि लेने से किया इनकार



बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो। लोक निर्माण मंत्री सतीश जारकीहोली ने कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें दी गई मानद डॉक्टरेट डी. लिट की उपाधि लेने से इनकार कर दिया है। इस संबंध में उन्होंने विश्वविद्यालय के कुलपति को पत्र लिखकर विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें दी गई मानद डॉक्टरेट की उपाधि वापस लेने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय इसे विदेशी न मानते हुए स्वेच्छा से लिया गया है और उन्हें उम्मीद है कि इस निर्णय का स्वागत किया जाएगा। मुझे मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान करके आपने समाज में मेरी जिम्मेदारी बढ़ा दी है। मैंने समाज सेवा में जो कार्यक्रम शुरू किए हैं, उन्हें सफल बनाने के लिए मैंने कई योजनाएं बनाई हैं। इसे लागू करने की मुझ पर बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि इसके लिए और समय की आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा कि 27 मार्च को राज्य मुक्त विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, कुलपति, प्रतिकुलपति और प्रबंधन बोर्ड के सदस्यों द्वारा विश्वविद्यालय की मानद डॉक्टरेट डी. लिट की उपाधि प्रदान करने के लिए वे प्रबंधन बोर्ड के प्रति बहुत आभारी हैं।

सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार, 2007 में जम्मू कश्मीर पुलिस में शामिल होने वाले मलिक इशफाक नसीर ने लश्करे तौयबा के हैडलर्स के साथ निकटता बढ़ाते हुए उसके साथ काम कर रहे थे और जम्मू क्षेत्र में हथियारों को ड्रोने से गिराने में की सुविधा प्रदान की थी। जांच से पता चला कि उन्होंने पोस्टा पार से जीपीएस-सक्षम हथियारों को कश्मीर तक पहुंचाने में मदद करने के लिए अपनी स्थिति का उपयोग किया और घाटी में सक्रिय आतंकवादियों को हथियारों को ले जाने में सहायता की। जबकि वर्ष 2011 से स्कूली शिक्षा विभाग में सेवा दे रहे अजाज अहमद ने कथित तौर पर पूरच में हिज्ब-उल-मुजाहिदीन संचालकों के साथ सक्रिय संपर्क बनाए रखा। नवंबर 2023 में उनके आतंकवादी लिंक सामने आए जब पुलिस ने एक नियमित जांच के दौरान उनके वाहन को रोक दिया और अपने टोयोटा फॉर्च्यूनर के अंदर हथियारों, गोला-बारूद और हिज्ब के पोस्टर पाए गए।

यूपी-स्वान 3.0 के जरिए ई-गवर्नेंस के नए-युग में होगी यूपी की इंट्री

लखनऊ, 03 जून (एजेंसियां)।

उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए प्रतिबद्ध योगी सरकार प्रदेश में ई-गवर्नेंस प्रक्रिया के आधुनिकीकरण व सुदृढ़ीकरण पर फोकस कर रही है। सीएम योगी का विजन है कि प्रदेश में ई-गवर्नेंस प्रक्रिया में शामिल विभिन्न प्रणालियों को न केवल धरातल पर उतारा जाए, बल्कि आधुनिकता का समावेश करते हुए उसे भविष्य की जरूरतों अनुरूप अपग्रेड किया जाए। इससे न केवल सरकारी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी बल्कि गुड गवर्नेंस का मार्ग भी प्रशस्त होता है। इसी कड़ी में एक बड़े प्रयास के तौर पर जल्द ही प्रदेश में उत्तर प्रदेश स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (यूपी-स्वान 3.0) को लागू करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उल्लेखनीय है कि यूपी-स्वान 3.0 प्रदेश में पहले से लागू यूपी-स्वान 2.0 का आधुनिक वर्जन है जो



कि राज्य में ई-गवर्नेंस के लिए आधारभूत संचार अवसंरचना के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (एनईजीपी) के तहत शुरू किया गया यूपी-स्वान पूरे राज्य में शासकीय स्तर पर सरकारी कार्यालयों को संचार से जोड़ने में सहायक रहा है। वहीं, यूपी-स्वान 3.0 के जरिए बेहतर सुरक्षा प्रणाली समेत कई खूबियों से लैस करने की तैयारी है जिससे

कनेक्टिविटी, मॉनिटरिंग व पारदर्शिता बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसे लागू करने के लिए आईटी व इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस क्रम में, उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम्स कार्प-रेशन लिमिटेड (यूपीडेस्क) को नोडल एजेंसी नियुक्त करते हुए प्रदेश भर में इंफ्रास्ट्रक्चर का ज़िम्मा सौंपा गया है। प्रदेश में यूपी-स्वान 3.0 के जरिए शासकीय स्तरों पर सरकारी

कार्यालयों को उन्नत इंटरफेस, बेहतर सिक्योरिटी व उत्तम कनेक्टिविटी से जोड़ने की तैयारी है। इस कड़ी में, यूपीडेस्क द्वारा एक कार्ययोजना तैयार की गई है। इसके अनुसार, पूरे राज्य में यूपी-स्वान 2.0 से जुड़ने से वंचित रह गए कार्यालयों को जोड़ने की तैयारी है। प्रदेश में स्टेट हेड कार्टर, कमिश्नर ऑफिस व जिला मुख्यालय पहले ही जोड़े जा चुके हैं। जबकि, प्रदेश के 351 तहसील मुख्यालयों में से 235 तथा 828 ब्लॉक मुख्यालयों में से 574 को जोड़ने में सफलता मिली है। ऐसे में, यूपी-स्वान 3.0 के जरिए 116 तहसील मुख्यालयों, 254 ब्लॉक मुख्यालयों तथा 75 विकास भवनों को जोड़ने की तैयारी है। यूपी-स्वान 3.0 का उद्देश्य शासन में आईटी सॉल्यूशंस के व्यापक उपयोग को बढ़ावा देकर विभागों में डिजिटल विभाजन को

कम करना है। यह इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को लागू करने के साथ ही उन्नत तकनीकों को प्रभावी बनाकर एक स्केलेबल, कॉन्फ़िगर करने योग्य व भविष्य की जरूरतों के अनुसार बुनियादी ढांचा प्रदान करेगा। यह स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क तकनीक को एकीकृत करेगा ताकि मल्टीप्रोटोकॉल स्विचिंग और इंटरनेट लीड्स लाइन्स में डायनामिक ट्रैफिक रूटिंग सुनिश्चित की जा सकेगी। इससे वर्तमान और भविष्य की दोनों मांगों को पूरा करने का फ्रेमवर्क तैयार होगा। यह सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट, ऑटोमेशन, रेगुलर मॉनिटरिंग, ईजी टू डिप्लॉय व एंड प्वाइंट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स (ईडीआर) से युक्त होगा। यूपी-स्वान 3.0 का उन्नत नेटवर्क फ्रेमवर्क उत्तर प्रदेश राज्य डेटा सेंटर (यूपीएसडीसी) में होस्ट किए गए महत्वपूर्ण सरकारी अनुप्रयोगों को कनेक्टिविटी प्रदान

करेगा, जो ई-ऑफिस और अन्य मिशन-महत्वपूर्ण ई-गवर्नेंस प्रणालियों जैसी आवश्यक सेव-1ओं का समर्थन करेगा। यह सरकारी संचालन और नागरिक सेवाओं दोनों की बदलती जरूरतों के अनुकूल होगा। इसके जरिए इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन, एंड टू एंड डाटा एनक्रिप्शन, नेक्स्ट जेनरेशन फायरवॉल्स (एनजीएफडब्ल्यू), इंटरनल डिटेक्शन प्रिवेंशन सिस्टम (आईएस-आईपीएस) तथा एडवांस्ड परसिस्टेंट थ्रेट (एपीटी) प्रोटेक्शन जैसी साइबर रक्षण प्रणालियां लागू हो सकेंगी। यह नई सुविधाओं को जोड़ने, एकीकृत करने, हाइब्रिड कनेक्टिविटी ऑप्शंस को बढ़ावा देने, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल करने और नेटवर्क ऑपरेशंस के सरलीकरण को बढ़ावा देकर ईजी एक्सेस को प्रमोट करेगा।

पर्यावरण दिवस 5 जून को प्लास्टिक खारिज करने का संकल्प लेंगे यूपी के बच्चे

लखनऊ, 03 जून (एजेंसियां)। 5 जून को पर्यावरण दिवस है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर बड़ी पहल शुरू की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आह्वान पर स्कूली बच्चों से लेकर युवा तक, सभी एंडिंग प्लास्टिक ग्लोबली का संकल्प लेकर पर्यावरण की रक्षा करेंगे। इसके तहत नुक़ड़ नाटक, भाषण, चित्रकला प्रतियोगिताओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाया जाएगा। पर्यावरण निदेशालय ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। पर्यावरण निदेशक की तरफ से इसके लिए समस्त जिलाधिकारियों को पत्र भी भेजा गया है। विभाग की तरफ से रीजनल साइंस सेंटर, अलीगंज लखनऊ में मुख्य आयोजन होगा। विश्व पर्यावरण दिवस इस वर्ष प्ला-स्टिक प्रदूषण को समाप्त करने, प्लास्टिक के उपयोग को कम करने व प्लास्टिक से बने सामानों का उपयोग न्यूनतम करने के उद्देश्य से मनाया जाएगा। उपनिदेशक श्रुति शुक्ला ने बताया कि पूरे प्रदेश में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। एंडिंग प्लास्टिक ग्लोबली थीम पर नुक़ड़ नाटक, भाषण व चित्रकला प्रतियोगिता का भी आयोजन होगा। कार्यक्रमों में स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ इस क्षेत्र में कार्य करने वाले विशेषज्ञ भी प्रतिभाग करेंगे। इस मुहिम का यंग फेस स्कूली बच्चों को बनाया जाएगा। उनके लिए प्रकृति को लेकर विभिन्न विषयों पर नुक़ड़ नाटक होंगे। नुक़ड़ नाटकों में दिखाया जाएगा कि प्लास्टिक का कचरा कैसे नदियों को मार रहा है और पर्यावरण पर प्रतिकूल असर दिखा रहा है। भाषण प्रतियोगिता में बच्चे बताएंगे कि प्लास्टिक का उपयोग कैसे न्यूनतम किया जाए। चित्रकला प्रतियोगिता में पर्यावरण से संबंधित अपने मनोभाव को पेंटिंग के जरिए उक़रेंगे। पर्यावरण निदेशक सुरांत शर्मा ने कहा, प्रदेश सरकार के निदेशन में युवाओं, बच्चों व जन-जन को सिंगल यूज प्लास्टिक के खतरों को बताने के साथ पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया जाएगा। एंडिंग प्लास्टिक ग्लोबली थीम पर स्कूलों बच्चों के मध्य जागरूकता कार्यक्रम, नुक़ड़ नाटक, भाषण, चित्रकला आदि प्रतियोगिता भी होगी। साथ ही पौधे लगाने और उन्हें संरक्षित के लिए भी बच्चों का आह्वान किया जाएगा।

यूपी में निवेश क्रांति के नायक बन रहे उद्यमी मित्र हैवल्स, शारदा ग्रुप, जेके सीमेंट, अमूल के निवेश से बदली तस्वीर

लखनऊ, 03 जून (एजेंसियां)।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उत्तर प्रदेश ने जिस रफ्तार से औद्योगिक विकास की दिशा में कदम बढ़ाए हैं, उसमें उद्यमी मित्र एक महत्वपूर्ण कड़ी बनकर उभरे हैं। इन प्रशिक्षित उद्यमी मित्रों ने न केवल प्रदेश में निवेश को गति दी है, बल्कि निवेशकों की समस्याओं का समाधान कर उन्हें विश्वास और सुविधा का माहौल भी दिया है।



उल्लेखनीय है कि योगी सरकार के एक जिला, एक उत्पाद से लेकर ग्लोबल इन्-वेस्टर्स समिट जैसी पहल तभी जमीन पर सफल हो पाई जब उद्यमी मित्रों ने अपनी भूमिका को पूरी निष्ठा, संकल्प और कार्यकुशलता से निभाया। आज यूपी में हो रहे रिकॉर्ड निवेश इसी भरोसे का परिणाम है, जहां सरकार और निवेशक के बीच सेतु का कार्य उद्यमी मित्र बखूबी निभा रहे हैं।

हैवल्स इंडिया लिमिटेड ने नोएडा में 879 करोड़ रुपए के आरएंडडी सेंटर के लिए निवेश किया, जो अब 2026 तक क्रियाशील होगा। यह तभी संभव हो पाया जब उद्यमी मित्रों ने समयबद्ध ढंग से प्रक्रियागत अड़चनों को दूर किया। इसी तरह, शारदा ग्रुप द्वारा आगरा में 600 करोड़ की लागत से विकसित हो रही हेल्थ सिटी परियोजना को भी नियामक स्वीकृतियों के

माध्यम से सुचारू रूप से आगे बढ़ाया गया। प्रयागराज में जेके सीमेंट की 400 करोड़ की सीमेंट परियोजना भूमि म्यूटेशन और सड़क मार्ग से जुड़ी बाधाओं से जुझ रही थी, लेकिन उद्यमी मित्रों के त्वरित हस्तक्षेप से यह चुनौती भी पार हो गई। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड की फतेहपुर परियोजना में 11 केवी की लाइन देरी का कारण बनी थी, जिसे उद्यमी मित्रों ने तत्परता से हल कर परियोजना को शुरू कराया। वहीं, बाराबंकी में डॉ. रमेश चंद्रा की 50 करोड़ की विनमैक्स एगो इंडस्ट्रीज और वाराणसी में अमूल के बोर्डिंग हाउस प्रोजेक्ट को भी उद्यमी मित्रों ने स्पष्टता और त्वरित अनुमोदनों के साथ आगे बढ़ाया।

इन्वेस्ट यूपी के तहत उद्यमी मित्रों ने जीबीसी-4 की परियोजनाओं का डेटा सटीक रूप से अपडेट किया है। इसके अतिरिक्त जीबीसी 5 के लिए एमओयू को

टैग करने और व्यवस्थित करने का कार्य भी तेजी से जारी है। वहीं, निवेशकों की समस्याएं प्राथमिकता के आधार पर सुनी, सुलझाई और आवश्यकता अनुसार उच्च अधिकारियों तक पहुंचाई जा रही हैं। उद्योग बंधु की बैठकें नियमित रूप से आयोजित कर निवेशकों से संवाद कायम किया जा रहा है। इसके साथ ही टीम ने इंडस्ट्री पायलट सर्वे, ईसी स्टेशन सर्वे और लैंड साइट विजिट्स जैसे कार्य निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरे किए हैं। प्रदेश सरकार ने उद्यमी मित्र योजना की शुरुआत ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पूर्व की थी, ताकि निवेशकों को सरकारी प्रक्रियाओं, अनुमतियों और समस्याओं के समाधान में एक समर्पित प्रतिनिधि मिल सके। ये मित्र विशेष रूप से प्रशिक्षित होते हैं और उन्हें विभिन्न जिलों व विभागों में नियुक्त किया गया है, ताकि वे निवेश संबंधी अड़चनों को दूर कर निवेशकों का मार्गदर्शन कर सकें। उद्यमी मित्र योजना ने उत्तर प्रदेश को निवेश के लिए एक भरोसेमंद और सक्षम राज्य के रूप में स्थापित करने में केंद्रीय भूमिका निभाई है।

यह पहल न केवल निवेशकों की सुविधा सुनिश्चित करती है, बल्कि प्रदेश सरकार के न्यू यूपी के विजन को धरातल पर उतारने का सशक्त माध्यम भी बन रही है।

वन्यजीवों को रोकने के लिए लग रही चेनलिंग और सोलर फेंसिंग

लखनऊ, 03 जून (एजेंसियां)।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में वन एवं वन्यजीव विभाग ने मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए व्यापक और प्रभावी कदम उठाए हैं।

इन प्रयासों में विशेष रूप से वर्ष 2023-24 से लेकर 2024-25 में लगभग 231 किलोमीटर चेन लिंग फेंसिंग और लगभग 41 किलोमीटर सोलर फेंसिंग के कार्य किए गए हैं।

जिससे न केवल वन्यजीवों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है, साथ ही वन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले ग्रामीणों और उनके पालतू जानवरों को भी सुरक्षा प्रदान की जा रही है। साथ ही विभाग द्वारा प्रशिक्षित किए गए बाघ मित्र, मानव वन्य जीव संघर्ष कम करने में उल्लेखनीय भूमिका निभा रहे हैं। साथ ही ट्रैकिंग डिवाइस, ड्रोन कैमरे, जीप-एस जैसी आधुनिक तकनीकों का प्रयोग कर वन क्षेत्रों की निगरानी और पेट्रोलिंग का कार्य एवं वन्य जीव संघर्ष को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो रहा है।

वन एवं वन्य जीव विभाग ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के अनुरूप वन्य जीव संरक्षण के साथ वन क्षेत्रों के समीप रहने वाले ग्रामीणों के जीवन और आजीविका को सुरक्षित करने के उद्देश्य से कई नवाचार अपनाये हैं। जिसमें से सबसे प्रभावी कदम प्रदेश के वन क्षेत्रों के चारों ओर बड़े पैमाने पर चेनलिंग फेंसिंग का

निर्माण है।

इस क्रम में वर्ष 2023-24 में लगभग 125 किलोमीटर चेनलिंग फेंसिंग और 21 किलोमीटर सोलर फेंसिंग का निर्माण किया गया, जबकि 2024-25 में 106 किलोमीटर चेनलिंग फेंसिंग और 20 किलोमीटर सोलर फेंसिंग स्थापित की गई। ये फेंसिंग वन्यजीवों को ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवेश करने से रोकने में कारगर सिद्ध हो रही हैं, जिससे फसलों और मानव जीवन को होने वाले नुकसान में कमी आई है। साथ ही इस फेंसिंग से ग्रामीण पालतू पशुओं के वन क्षेत्रों में प्रवेश और उनको शिकार से बचाने के लिए होने वाले मानव वन्यजीव संघर्ष में भी उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है।

मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए वन एवं वन्य जीव विभाग का प्रभावी कदम बाघ मित्र का चयन और प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना साबित हुआ है।

ये बाघ मित्र स्थानीय ग्रामीणों को जागरूक करने और वन्यजीवों के साथ सुरक्षित सह-अस्तित्व को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इनके माध्यम से ग्रामवासियों के साथ नियमित बैठकें और संवाद आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें वन्यजीवों से बचाव के उपाय, उनकी गतिविधियों की जानकारी और आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई जैसे विषय शामिल हैं।

बाघ मित्रों का चयन विशेष रूप से टाइगर रिजर्व के निकटवर्ती ग्रामों के लिये

किया गया है, इसके साथ ही इटावा के लायन सफारी के लिए भी बाघ मित्रों का चयन किया गया है। यह पहल न केवल जागरूकता बढ़ाने का काम रही है, साथ ही स्थानीय समुदायों और वन एवं वन्य जीव विभाग के बीच विश्वास बढ़ाने का कार्य भी कर रही है।

प्रदेश के वन प्रभागों में मानव-वन्यजीव संघर्ष रोकथाम के लिए राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से प्राप्त धनराशि का उपयोग विभिन्न उपकरणों की खरीद में किया गया है। इन उपकरणों में निगरानी उपकरण, ट्रैकिंग डिवाइस और अन्य तकनीकी संसाधन शामिल हैं, जो वन्यजीवों की गतिविधियों पर नजर रखने में सहायक हैं।

इसके अतिरिक्त, वन क्षेत्रों और सीमावर्ती इलाकों में सघन गश्त की जा रही है, ताकि वन्य जीवों के मानव बस्तियों में प्रवेश को रोका जा सके। वन क्षेत्र के बाहर विचरण करने वाले वन्यजीवों की नियमित ट्रैकिंग के लिए आधुनिक तकनीकों ड्रोन, जीपीएस ट्रैकिंग और कैमरा ट्रैप का उपयोग किया जा रहा है।

इस ट्रैकिंग के माध्यम से न केवल वन्यजीवों की गतिविधियों पर नजर रखी जाती है, बल्कि आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई में भी की जाती है। वन एवं वन्य जीव विभाग के इन कदमों से न केवल जैव-विविधता संरक्षित हो रही है, बल्कि ग्रामीण समुदायों को सुरक्षा और आजीविका भी मिल रही है।

गांव-गांव बनेंगे समृद्ध, क्लस्टर मॉडल से बदलेगी किसानों की तकदीर

लखनऊ, 03 जून (एजेंसियां)।

योगी सरकार किसानों की आय बढ़ाने और उनके जीवन को समृद्ध बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते जा रही है। अब प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग को व्यापक स्तर पर लागू किया जाएगा। इसके तहत एक ग्राम पंचायत एक क्लस्टर अभियान चलाया जाएगा, जिससे किसानों की आमदनी ही नहीं, बल्कि उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में भी बड़ा परिवर्तन आएगा।

हर क्लस्टर 50 हेक्टेयर भूमि में फैला होगा, जिसमें कम से कम 125 किसानों को शामिल किया जाएगा। पहले साल 7.16 लाख रुपए और दूसरे साल 6.83 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा, जो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने में मददगार होगा। किसान फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन (एफपीओ) से भी जुड़ेंगे, जिससे उन्हें फार्म मशीनरी बैंक, कस्टम हायरिंग सेंटर, वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज और मार्केटिंग की अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। प्रदेश सरकार की योजना है कि वर्ष 2025-26 तक बड़ी संख्या में क्लस्टर विकसित कर लाखों किसानों को



इससे जोड़ दिया जाए। जिससे न केवल खेती की लागत घटेगी, बल्कि उत्पादकता और आय दोनों में वृद्धि होगी।

प्राकृतिक खेती से जुड़कर किसान न केवल जैविक उत्पाद उगाएंगे, बल्कि उन्हें बाजार में अच्छे दाम भी मिलेंगे। इससे ग्राम पंचायतें आर्थिक रूप से सक्षम होंगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार का यह अभियान किसानों के लिए वरदान साबित होगा। क्लस्टर आधारित नेचुरल फार्मिंग मॉडल से जहां खेती लाभकारी बनेगी, वहीं ग्राम पंचायतें कृषि नवाचार का केंद्र बनेंगी। यह योजना न केवल खेतों की सेहत सुधारेगी, बल्कि किसानों के चेहरों पर भी मुस्कान लाएगी।

लखनऊ, 03 जून (एजेंसियां)।

योगी सरकार योग के माध्यम से जनमानस में स्वास्थ्य और सशक्त जीवनशैली को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय कदम उठा रही है। इसी के तहत प्रदेश भर में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 15 जून से 21 जून तक योग सप्ताह मनाया जाएगा। इस दौरान जनपद, तहसील, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर सामूहिक योग कार्यक्रम, सेमिनार, कार्यशाला, संगोष्ठी, भाषण प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता, निबंध लेखन एवं स्लोगन प्रतियोगिता सहित कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा।

प्रमुख सचिव आयुष रंजन कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर योग के प्रचार-प्रसार के लिए 5000 प्रशिक्षित योग ट्रेनर तैयार

किए गए हैं, जो प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में योगाभ्यास करवाएंगे। योग प्रशिक्षकों और आयुष महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों, प्रबंधकों द्वारा विभिन्न समितियों का गठन कर योग सप्ताह की व्यापक तैयारी की गई है। इन समितियों के माध्यम से चिकित्सा शिक्षा महाविद्यालय, व्यवसायिक शिक्षा महाविद्यालय एवं अन्य महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के बीच योग से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य आयोजन में देश के 1,00,000 स्थानों पर सामूहिक योगाभ्यास का आयोजन होगा, जिसमें प्रदेश के 4,075 स्थानों पर कॉमन योग प्रोटोकॉल के अनुसार 21 जून को सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम होंगे।

इस मौके पर पूरे प्रदेश में एक साथ वृहद स्तर पर योगाभ्यास

प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही यह आयोजन देश के प्रत्येक जिले में कवर करते हुए अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विशेष योग संगम कार्यक्रम आयोजित करने की योजना है।

सीएम योगी की मंशा के अनुरूप प्रदेश में योग को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय निकायों के माध्यम से देश भर में 1,000 योग पार्क स्थापित किए जाएंगे। मंडल मुख्यालय वाले जनपदों में 3 और अन्य जनपदों में 2-2 योग पार्क चिन्हित किए गए हैं, जिन्हें नगर विकास विभाग के समन्वय से विकसित किया जाएगा। इन योग पार्कों में पालिकाओं और पंचायतों का सहयोग लिया जाएगा ताकि क्षेत्र के अधिक से अधिक लोग योगाभ्यास कर सकें। योग के सिद्धांतों को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ते हुए एक नई

पहल भी शुरू की गई है। इसमें प्राकृतिक स्थानों पर योगाभ्यास के साथ-साथ वृक्षारोपण और सफाई अभियानों को भी जोड़ा जाएगा। इस योजना के तहत अमृत जलाशयों के किनारे योग सत्र आयोजित किए जाएंगे और पौधरोपण का कार्यक्रम भी होगा। प्रदेश की प्रमुख नदियों, झीलों और पार्कों में योग सत्र के साथ-साथ स्वच्छता कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में आयुष विभाग की बैठक में कहा कि योग सिर्फ एक व्यायाम नहीं, बल्कि यह जीवन का एक तरीका है जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को बढ़ाता है। उन्होंने कहा कि योग के माध्यम से हम अपनी जीवनशैली में सुधार कर सकते हैं, बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ा सकते हैं और समाज

में समरसता एवं शांति स्थापित कर सकते हैं। ऐसे में योगी सरकार ने प्रदेश के हर जिले तक योग की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए व्यापक तैयारी की है और इसके लिए प्रशिक्षित योग प्रशिक्षकों की भी व्यवस्था की गई है। योग सप्ताह के अंतिम दिन 21 जून को पुरस्कार वितरण एवं प्रमाणपत्र वितरण समारोह भी आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा 1 जून से आयुष चिकित्सकों एवं योग विशेषज्ञों द्वारा टीवी और दूरदर्शन पर जागरूकता कार्यक्रम भी प्रसारित किए जाएंगे, जिनमें विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं के लक्षण और प्रबंधन पर जागरूकता बढ़ाई जाएगी। साथ ही लोगों को व्यक्तिगत एवं सामूहिक योगाभ्यास की फोटो प्रारत सरकार के सूेी पोर्टल पर प्रतिदिन अपलोड करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा।



संपादकीय

मेहमाननवाजी का नया दौर

मेहनत को मार्किटिंग के जरिए सुधारने की एक और कोशिश हिमालयलवले ने शुरू की है। निगम ने पहले होटललवले पर्यटन को प्रोफेशनल आधार देने के लिए निजी कंपनी से अनुबंध किया और अब सार्वजनिक उपक्रमों के साथ पैकेज डील का करार किया है। दरअसल पहली बार निगम ने अपनी रणनीति में व्यापारिक उद्देश्य जोड़ते हुए निजी क्षेत्र के सलीके सीखे हैं। ओएनजीसी, दिल्ली मेट्रो, सेल, गेल और दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जैसी संस्थाओं के साथ एमओयू करके निगम ने महमानवानजी का का दायरा बढ़ा और चुस्त-दुरुस्त किया जा रहा है। हिमालयलवले पर्यटन संघर्षों में खुद को रेखांकित करने की साझा शक्ति का कमाल है कि सरकार उच्छ्वास में उठी है। राहों में नई मंजिलें खोज लीं। अपनी नई हैसियत में पर्यटन के कुन्ने को प्रतिष्ठित करने की कोशिश पहली बार शुरू हुई है, तो निगम के प्रबंध निदेशक डा. राजीव कुमार के नेतृत्व की प्रशंसा करनी होगी। ये दायरे आगे चलकर और बड़े तथा सशक्त हो सकते हैं। भ्रमण की बदलती जरूरतों तथा सूचक की नई तलाश के बीच पर्यटन विकास निगम की संघर्षाओं का एक स्थायी जलवा तो है ही, लेकिन इसका विस्तार करते हुए सैलानियों के रुकने के टौर बढ़ाने के लिए पैकेज के भागीदार भी जोड़ने होंगे। मसलन को टूरिज्म की साइट्स अगर लीज पर जा रही हैं, तो पर्यटन निगम को इसमें भागीदारी जोड़ते हुए अपनी प्रोफेशनल चमत्कारी दिखानी होगी। पर्यटन निगम को एचआरटीसी के अलावा प्रदेश में आ रही पड़ोसी राज्यों के पर्यटन उपक्रमों के साथ मिलकर यात्रा विस्तार की योजनाएं बनानी चाहिए। अमृतसर, आनंदपुर साहिब, हरिद्वार और ऐसे अनेक धार्मिक स्थलों से आ रहे पर्यटकों को हिमालयलवले में लाने व ठहराने के लिए सभी राज्यों के परिवहन उपक्रमों के साथ पैकेज बनाए जाएं, तो पर्यटन की एक साझी विरासत बनेगी।

हट के या राजस्थान परिवहन के साथ हिमालय यात्रा का अनुबंध, एक पैकेज डील की तरह हो सकता है, जहां अपने-जाने के टिकट के साथ कुछ डिस्काउंट पर सस्तरकारी होलाओं की बुकिंग तथा साइट सीईई का पूरा पैकेज नथी हो। निजि वोल्वो बसों के तसदस हिमालयी पर्यटन की ब्रांड है, लेकिन सस तथस है अन्धनिज सस्तरकारी होला, कमाई का एक बड़ा स्रोत गंवा रहे हैं। अगर निजि वोल्वो बसों के संचालन, मार्किंग तथा बोर्डिंग के स्थल पर्यटन यात्रास निगम अपनी देखरेख या अपने परिसरों से अनुमोदित करे, तो यात्री सुविधाओं के स्थायी पते के कारण ये संपर्कित यात्रा बहतर ढंग से इस्तेमाल होगी। कुछ माल, पेट्रोल पंप व होटल इकाइयां निजि वोल्वो बसों के आगमन तथा प्रस्थान के कारण पर्यटकों की पसंद बन गए हैं। ऐसे में पर्यटन निगम भ्रमशाला जैसे स्थान पर पर्यटक वाहनों व निजि वोल्वो बसों के आगमन तथा प्रस्थान के लिए परिसर बना कर, हर दिन सैकड़ों पर्यटकों के लोहराव तथा टूरर प्रोग्राम की मेजबानी कर सकता है। पर्यटन विकास निगम को अपनी मार्किटिंग के पार्टनर खोजते हुए एचआरटीसी, राज्यों के परिवहन उपक्रमों के अलावा रेलवे तथा एयरलाइनों के साथ आगमन-प्रस्थान के अलावा राज्य में विश्राम, मनोरंजन व सक्न के पैकेज शेर करने चाहिए। मसलन अंब-अंदोरा तथा धानकोटक तक बंद भारत ट्रेनों से आ रहे पर्यटकों को प्रमुख पर्यटक केंद्रों तक पहुंचाने, ठहराने तथा धुमाने की जिम्मेदारी का विस्तार तथा अनुबंध करना होना। इसी तरह हवाई उड़ानों के साथ हिमालय टूरर के अलग-अलग पैकेज बनाकर राज्य के पूर्ण पर्यटन की मार्किटिंग शुरु करनी चाहिए। पर्यटक को राज्य के उपक्रमों के साथ जोकर सुरक्षा, ईमानदारी व बेहतर मेहमाननवाजी का एहसास कराने से पर्यटन का नया दौर शुरू हो सकता है।

आप का नजरिया

यह वक्त एकजूटता का है

1947 -48 के भारत-पाक युद्ध में हमारे करीब 6000 जवान 'शहीद' हुए थे। 1965 के युद्ध में यह संख्या 3500 के करीब रही और 1971 के भारत-पाक युद्ध में भी करीब 3000 सैनिक शहीद हुए। 1999 के कारगिल युद्ध में भी यह संख्या 527 तक पहुँच गई। देश के अनुभवी रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, विभिन्न युद्धों, संघर्षों या किसी अन्य ऑपरेशन के दौरान 15,000 से अधिक सैनिक शहीद हो चुके हैं। क्या देश को यह एहसास है कि कितने परिवार कालखंड में अधिकतर वह भी सत्तारूढ़ या? क्या कोअ्रेस देश को बताएगी कि इन शहीद सैनिकों को लेकर संसद के कितने विशेष सत्र बुलाए गए? शहादत के आंकड़ों किसी संसदीय रिकॉर्ड में दर्ज हैं? कितने जांबाज जवान घायल हुए होंगे और अपाहिज हुए गए होंगे? क्या देश को यह भयानक यथार्थ किसी ने बताया है? लोकतंत्र और सरकार की गतिविधियों, कारवाइयों को जाने का अधिकार दिनांक 18 सितंबर 1947 को सही नहीं हो सकता। युद्ध और सामान्य, सार्वजनिक मुद्दों के बीच गहरे अंतर है। सवाल है कि कोअ्रेस यह जान कर कौन-सा राबनीतिक लक्ष्य हासिल करने लेगी कि भारत-पाक के हालिया संघर्ष के दौरान हमारे कितने लड़ाकू विमान गिराए गए? हमारी नुकसानों में आतंकियों के 9 बड़े ठिकानों मिट्टी में मिला दिए, करीब 170 आतंकियों को ढेर भी किया, पाकिस्तान के महत्वपूर्ण एयरबेस, रडार सेंटर और वायु रक्षा प्रणालियाँ इस करतब तबाह कर दी गईं कि 4-5 साल तक नुकसान युद्ध और सैनिकों को लोच भी नहीं सकता। क्या कोअ्रेस खुश नहीं है कि हमारी सेनाओं और नये तैय लक्ष्य हासिल किए और दुनिया के विशेषज्ञ भारत की निर्णायक जीत के विश्लेषण कर रहे हैं? अब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) की आड़ में छिपकर कोअ्रेस मोदी सरकार और सेना को निशाना बनाने पर अमादा है। बेवकूफ सीडीएस जनरल अलिन चौहान ने एक साक्षात्कार में स्वीकार किया है कि हालिया संघर्ष में शुरूआत के दो दिनों में हमें हवाई नुकसान उठाना पड़ा। नंबर अहम नहीं हैं, लेकिन हम गलतियाँ सुधारी और अपने दरांगे पर हमला बल कर उसे तबाह करने कर दिया। डीजीएमओ (जंग ऑपरेशन) एयर मार्शल एंके भारती ने भी लगभग यही बात कही कि जंग में नुकसान अपरिहार्य हैं, लेकिन सीडीएस ने पाकिस्तान के दुश्मन, 5 रफेल विमान गिराने के दावे को सिर से खारिज कर दिया। कोअ्रेस सीडीएस के बयान का एक छोटे पकड़ कर सवाल करते हुए संदेह जताने पर व्यर्थ रह चुके हैं? उसकी विदेश के विशेष सत्र बुलाने में क्या दिलचस्पी है? हम पहले भी कह चुके हैं कि यदि सामूहिक विषण्ण सत्र को मांग कर रहा है, तो सरकार को आमंत्रित करना कुछ पहली ही बयान लेना चाहिए, लेकिन जंग कोअ्रेस चाहती है कि प्रधानमंत्री मोदी सीडीएस के बयान पर संसद में स्पष्टीकरण दें। कोअ्रेस को पता होना कि अभी 'ऑपरेशन सिंदूर' स्थगित है, खतम नहीं हुआ है। युद्ध की रणनीति अति गोपनीय विषय है, उसे संसद के मंच पर भी सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। कोअ्रेस उन्नीसवीं रणनीति की ओर संकेत किया है। क्या प्रधानमंत्री के स्पष्टीकरण के जरिए कोअ्रेस उन्नीसवीं रणनीति का खुलासा करवा देना चाहती है, जो पाकिस्तान के लिए फायदेमंद हो सकती है। पाकिस्तान हमारी सैन्य रणनीति जानने के बाद अपनी रणनीति दोहरा देना सकता है। हमारा सवाल है कि क्या कोअ्रेस का अस्तित्व भारत के अस्तित्व से भिन्न है? उसने कारगिल युद्ध के बाद विशेषज्ञ समिति की तर्ज पर नहीं समीक्षा-समिति बनाने की भी मांग की है। इस संदर्भ में नेता प्रतिक्ष राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर बातचीत कर सकते हैं। सार्वजनिक मंच पर शोर मचाने और प्रधानमंत्री पर देश को मुमताश करने जैसे आरोप लगाने से हासिल क्या होगा? दुश्मन ही छिल्ली उड़ाएगा। यह युद्ध-सा माहौल है, लिहाजा कोअ्रेस को ऐसा जरूरी रवैया नहीं अपनाना चाहिए। देश और सेना उसकी भी है।

लाख खामियों के बावजूद आधुनिक दुनिया अपने आप को लोकतांत्रिक व्यवस्था कहलवाना पसंद करती है

वैश्विक विस्मृति के शिकार तियानमेन चौक के शहीद

वर्तमान युग लोकतंत्र का है, इस प्रणाली को लाख खाँियों के बावजूद आधुनिक दुनिया अपने आप को लोकतांत्रिक व्यवस्था कहलवाना पसंद करती है। यहाँ तक कि मजहबी राजनीतिक व्यवस्था वाले देश भी अपने नाम में किसी न किसी तरह लोकतंत्र शब्द को शामिल करके स्वयं को प्रगतिशील साबित करने का प्रयास करते हैं। पर आश्चर्य की बात है कि लोहारवणवादी कम्युनिस्ट व्यवस्था को जबरन ढो रही चीन की जनता ने आज से चार दशक पहले लोकतंत्र के पक्ष में आवाज उठाई तो उस टैकों ने रौंद दिया और आज लोकतांत्रिक वैश्विक समाज उस घटना को लगभग भूल सा गया लगता है। दरअसल 4 जून, 1989 में चीन के बीजिंग कितायानमेन चौक बड़े पैमाने पर विपक्षी प्रदर्शनों का केन्द्र बना, जिसे चीन के कम्युनिस्ट शासकों ने बुरी तरह कुचल दिया। इसकी पुच्छभूमि में जाएँ तो पता चलता है कि 1980 के दशक में चीन बड़े बदलावों से गुजर रहा था। सतारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ने कुछ निजी कंपनियों और विदेशी निवेश को अनुमति देना शुरू कर दिया। चीनी नेता डेंग जियाओपिंग को इससे अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने और लोगों को जीवन स्तर ऊपर उठने की आशा थी। इस कदम से राजनीतिक खुलेपन की उम्मीद भी गयी, लेकिन उस समय कम्युनिस्ट पार्टी दो भागों में बंट गई। एक वर्ग वो तो तौर परिवर्तन की मांग कर रहा था, तथा दूसरा वो कठोर राज्य नियंत्रण बनाए रखना चाहता था। इस दौरान छत्रों के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। इसमें भाग लेने वालों में वे लोग शामिल थे जो विदेश में रह चुके थे और नवविचारकों का युवा उच्च जीवन स्तर से परिचित थे। 1989 में अधिक राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग के साथ विरोध प्रदर्शन बढ़ गये। प्रदर्शनकारियों को एक प्रमुख राजनीतिज्ञ हुआ ओबांग से प्रोत्साहन मिला, जिन्होंने कुछ आर्थिक और राजनीतिक परिणतों की देखरेख की। दो वर्ष पहले राजनीतिक विरोधियों ने उन्हें पार्टी के शीर्ष से हटा दिया था। अप्रैल में हू की मौत हो गई, उनके अंतिम संस्कार के दिन हजारों लोग एकत्रित हुए और उन्होंने अधिक अभिव्यक्ति की मांग में स्वतंत्रता तथा कम संसेसरियता की मांग की। अगले सप्ताहों में प्रदर्शनकारि कितायानमेन चौक पर एकत्र हुए, जनकी अनुमानित संख्या लाख लाख तक थी। तत्कालीन कम्युनिस्ट सरकार ने इस दौरान न केवल हजारों निर्दोष नागरिकों, विशेषकर छात्रों और श्रमिकों का निर्मम दमन किया गया, बल्कि करोड़ों चीनी नागरिकों के मौलिक संवैधानिक अधिकारों को भी रौंद दिया। 3-4 जून की रात, चीन की जनप्रति सेना ने बख़्तरबंद टैंकों और हथियारों से छात्रों पर हमला किया। हजारों की संख्या में निर्दोष लोगों की हत्या

A large crowd of people is gathered in Tiananmen Square, with the Monument to the People's Heroes in the background. The square is filled with people, and many red flags are visible. The monument is a tall, grey, rectangular structure with a large, ornate base. The sky is overcast.

गालीबार्थी शुरू कर दी, जिससे प्रार्थीक शिष्टाचार के अनुसार 35-36 लोग मरण पाए। लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी। 14 जून की सुबह करीब 4 बजे, जब तियायमेन चक्रे पर हजारों की संख्या में निहत्थे छात्र, नागरिक, बच्चे और बुजुर्ग शांतिपूर्वक लोकतंत्र और पारदर्शिता की मांग को लेकर एकत्र थे, तब कम्युनिस्ट सरकार ने क्रूरतामय रूप का प्रदर्शन किया। सरकार ने न सिर्फ टैंक और हथियारों से लैस जवानों को तियायमेन चक्रे पर भेजा, बल्कि लड़ाखू विमानों तक की तैनाती की। बिना किसी चेतावनी के गोलीया बरसाई गई। निर्दोष लोगों को कुचला गया, दौड़ते बच्चों को निशाना बनाया गया, और चौक को रक्तर्जित कर दिया गया। यह कार्रवाई सिर्फ एक नरसंहार नहीं बल्कि लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की भावना पर एक संगठित, राज्य-प्रयोजित प्रहार था। बीजिंग की सड़कों पर मानव रक्त की नदियाँ बह रही थीं। यह कोई युद्ध का मैदान नहीं था, बल्कि एक शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक प्रदर्शन के खिलाफ राज्य द्वारा चलाया गया सुनिश्चित नरसंहार था। चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने छात्रों और नागरिकों की शांतिपूर्ण मांगों का उत्तर देकों और गोलीया से दिया। कुछ के अंश में बीजिंग की सड़कों पर टैंक गर्जन करने लगे और राख के धोंधे में लगभग 10,000 निर्दोष लोगों की जानें चली गईं। चीन की सरकार अनुसार, दोसी लोगों और तीन हजार घायल हुए। तियायमेन नरसंहार को लेकर वर्षों तक चीन सरकार ने मृत्यु संख्या को लेकर पूर्ण गोपनीयता बनाए रखी, लेकिन समय के साथ कुछ अंतरालीय दस्तावेज सामने आए, जिनमें इस भयावह घटना की असली स्वीय उजागर की। चीन में नक्तीन ही प्रिडिश राजतु एलन डॉनल्ड ने 1989 में लंदन भेजे अपने एक गोपनीय टेलीग्राम में स्पष्ट रूप से कहा था कि इस सीमा कार्रवा में कम से कम 10,000 लोगों की मृत्यु हुई। यह टेलीग्राम घटना के 28 वर्ष बाद संवर्जित हुआ। हॉन्गकॉंग बैप्टिस्ट विश्वविद्यालय में चीनी इतिहास, भाषा और संस्कृति के विशेषज्ञ ज्यु पिए कवेस्टन ने भी इस टेलीग्राम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 'ब्रिटिश राजनयिकों द्वारा भेजे गए आँकड़े हैं और इन्हें सही नहीं किया जा सकता।' प्रसिद्ध चीनी लेखक और सामाजिक आलोचक लियाओ इङ्गु ने तियायमेन नरसंहार को लेकर अपनी लेखनी के माध्यम से चीनी

सत्ता की कूरता को बेनकाब किया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि चीन अपने पूर्ण दुर्गति के लिए एक गंभीर खतरा बन चुका है।

‘बॉल्स ऑफ अपियम’ नामक अपनी पुस्तक में, जो विश्व रूप से प्रसिद्ध है, तियानमेन चौक की घटना पर आधारित है, उन्होंने लिखा,

‘लोकतंत्र की स्थापना के लिए संघर्ष कर रहे हजारों लोगों को सेना ने निर्भयता से कुचल दिया।’ यह पुस्तक न केवल चीन में प्रतिबंधित कर दी गई, बल्कि अलाओ को इस विचारधारा के खिलाफ बोलने के कारण जेल, गुप्त निगरानी और अंततः निर्वासन तक का सामना करना पड़ा। इस घटना के बाद भी चीनी सरकार ने नैतिक दमनात्मक रवैया छोड़ा नहीं बल्कि अत्याचारों की सारी सीमाएँ लांघ दी। 6 जून नरसंहार के तुरंत बाद चीन में स्थित विदेशी शरणार्थियों ने अपने-अपने नागरिकों को सुरक्षा कार्यों में देश छोड़ने के निर्देश जारी किए ताकि इस घटना पर पर्दा डाला जा सके।

16 जून को आंदोलन का नेतृत्व करने वाले छात्र नेताओं की अध्यक्षता गिरफ्तारी शुरू हुई। विभिन्न विश्वविद्यालयों से जुड़े 10000 से अधिक छात्र नेताओं को चिन्हित कर हिरासत में लिया गया। अगले दिन 17 जून बीजिंग में 8 नागरिकों को मृत्युदंड दिया गया। 20 जून को चीन ने सभी देवता वीजा पर रोक लगा दी। यह निर्णय अंतर्राष्ट्रीय लया गया ताकि कोई भी आंदोलनकारी देश छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय समर्थन न प्राप्त कर सके, और विरोध की आवाज को सीमा के भीतर ही दबा दिया जाए। वैसे तियानमेन नरसंहार वामपंथी विचारधारा के चरित्र का कोई अपवाद नहीं, बल्कि उसकी सतत अमानवीय प्रवृत्तियों की ही एक कड़ी है। इतिहास के पन्ने पलटने पर स्पष्ट होता है कि वामपंथी अधिनायकवाद का पूरक नरसंहार ऐसे ही संविधान-विरोधी अत्याचारों और दमन की घटनाओं से अटा पड़ा है। लेनिन के नेतृत्व में ‘बोल्शेविक क्रान्ति’ के बाद लाखों विरोधीयों का दमन, स्टालिन के ‘प्रेत पर्व’ के दौरान अनुमानित दो करोड़ से अधिक लोगों की हत्या, और माओसे के द्वारा के ‘प्रेत लीला फारवर्ड’ और ‘कल्चुरल रेवोल्यूशन’ में करोड़ों लोगों की मौतें, यह दिखाती हैं कि वामपंथी शासन अक्सर आलोचना और विरोध को कुचलने के लिए नरसंहार और दमन को ही नीति का रूप देता है। यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि भारत के नौ नीति विचारक और संघटन भी उन्हीं बौद्धिक व्यक्तित्वों लेनिन, माओ और स्टालिन से वैचारिक प्रेरणा लेते रहे हैं, जिनकी नीतियों अत्याचार, दमन और हिंसा से जुड़ी रही हैं। चाहे वह बंगाल और केरल की वामशासित सरकारों में राजनीतिक हिंसा का इतिहास लें, या फिर नक्सलवाद और अर्धन नक्सलियम के माध्यम से राज्यविरोधी हिंसक विधिविधायें, इन सब वामपंथी विचारधारा की भूमिका बार-बार सामने आती रही है। भारत-चीन युद्ध के दौरान जैसे भारत के कम्युनिस्टों ने दुश्मन देश का समर्थन करके अपने चरित्र का प्रमाण दिया उसी तरह तियानमेन चौक नरसंहार पर भी उन्होंने चीन को मूक समर्थन दिया।

देश

दुनिया से

विकास के विनाशकारी प्रभाव

मानव

प्रदत्त जीवनदाया तत्त्वों का विनाश बढ़ती ही जा रहा है। हालाँकि प्रकृति मित्र विवास के मॉडल विकासित करने से पहले और प्रयास किए जा रहे हैं, किन्तु जिन ग्रामों के विकास का विनाश किया जा रहा है, उसकी भरपाई करना असंभव होता जा रहा है। हवा, पानी और भोजन जीवन की सबसे मूल जरूरतें हैं। हवा प्रदूषण इतने हद तक बढ़ गया है कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में चैबर बनने जा रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के चलते परती पर पानी के भंडार खतरे में पड़ गए हैं। हिमनदों के पिघलने की गति बढ़ती जा रही है जिसके चलते आने वाले 40-50 वर्षों में ग्लेशियर समाप्त होने के कारण पर होगा। अमरीका के रीजिंग से लेकर यूरोप की ऐस्पेस, काकेशस, और भारत की हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं हिमनद मुक्तिवर्धन होने वाली हैं। विज्ञान तापक्रम 'साइंस' के मुताबिक यदि हम वैश्विक तापक्रम वृद्धि को औद्योगिक क्रांति के बाद से 2 डिग्री सेंटी ग्रेड के भीतर नहीं रोक सके तो विश्व के ग्लेशियरों में सदी के अंत तक 10-15 फीसदी ही बच पाएंगे रहेंगे। इससे पानी की आपूर्ति करने वाली सहोदारी नदियाँ मौसमी बन कर रह जाएंगी जिनमें बारिशानी पर ही पानी होगा, या थोड़ा बहुत वनों द्वारा संरक्षित जल पर ही आबादी को निर्भर रहना पड़ेगा। भूजल की स्थिति भी अच्छी नहीं है। भारत में 45 फीसदी क्षेत्र भूजल के अधिक दोहन के कारण लाल सूखे में आ गए हैं। हिमनदों के जल पिघलने के कारण हिमालयी क्षेत्रों में हिमनद जनित झीलें बन रही हैं। हिमनदों की वर्षेक फलमले के साथ टूट कर पवती बना देती हैं घाटियों में गिर कर बर्फीले क्षेत्रों के बांध बना देती हैं, जिसमें हिमनदों का पानी जमा होता रहता है और जब पानी की मात्रा जांती है की दीवार की झेलने की शक्ति से ज्यादा हो जाती है, तब ये हिमनद बांध टूट कर निचले क्षेत्रों में बाढ़ लाकर बरसित तबाही का कारण बनते हैं हिमाचल में 90 के दशक में

पाहू से आई बाढ़ और उत्तराखंड में विष्णुगाढ़ बाढ़ नाजा उदाहरण हैं। हिमालय में इस समय 28000 के करीब हिमनद झीलें बन चुकी हैं जिनमें से बहुत सी खतरनाक साबित हो सकती हैं। उपजाऊ जमीनें अत्यधिक उपज लेने के चक्कर में रासायनिक खादों और कीटनाशक और खरपतवार नाशक दवाइयों के प्रयोग के कारण अपनी शक्ति खोती जा रही हैं। यानी



जिहाद करने के लिए सबसे जल्दी तीनों ताल खबरों की चपेट में है। आम जनपथ परिवर्तन के कारण प्रक्रांतिक अणुओं का क्रम भी बहुत जा रहा है। अति वृद्धि और अनावृष्टि का क्रम आम हो गया है। इस वर्ष हिमाचल में मार्च में ओसल से कम बारिश हुई है। जब बारिश होती है तो बहुत भारी बारिश होती है। हिमाचल और उत्तराखण्ड में पिछले दो वर्षों से बरसत में भारी तबाही हो रही है। गत वर्ष हिमाचल में 450 के लगभग लोग अकाल मृत्यु का प्रारंभ बन गए थे। इस वर्ष बहुत महीने ही कुल्लू और चंबा जिलों में बादल फटने की घटनाएं हो चुकी हैं, जिससे जन-पथ की हानि हुई है। भारतीय ऊर्जा, पर्यावरण एवं जल परिषद ने इस वर्ष देश के 57 फीसदी जिलों को बीजगण 76 फीसदी आबादी को निवास है, अत्यंत जोषण गमी की चपेट में आने की चेतावनी दी है। 1993 से 2022 के बीच भीषण खरास सूचकांक 2025 के अनुसार सौमन की भारी मार झेलने वाले देशों में भारत छठे स्थान पर है। 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2022 के बीच 55 फीसदी देशों में बारिश में भारी वृद्धि दर्ज की गई। वैश्विक

तपमान में अप्रत्याशित वृद्धि के कारण ही यह स्थिति बनी है। तापमान में वृद्धि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में वृद्धि के कारण हुई है। इन गैसों के उत्सर्जन में वृद्धि अंधाधुंध निर्माण कार्यों में वृद्धि के कारण हुई है। अत्यधिक ऊर्जा की मांग के कारण जीवाश्म ईंधनों के प्रयोग में वृद्धि हो रही है। निर्माण कार्यों के कारण ग्रीन हाउस गैसों को प्रचुषित करने नियंत्रण करने वाले वना का भी बहुत कटाव हो रहा है। भारतवर्ष चीन और अमरीका के बाद सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश बन गया है। गत वर्षों में भारत कोयले के खनन को लगभग 5 फीसदी बढ़ा चुका है। जरूरत है इसे कम करने जाने की है। हालाँकि स्वच्छ ऊर्जा के लिए सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए अच्छे प्रयास हुए हैं। 2015 में सौर ऊर्जा का कुल ऊर्जा उत्पादन में योगदान 0.5 से बढ़ कर 5.8 फीसदी हो गया है। इस समय भारत की स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता 73 गीगावाट है, जो विश्व स्तर पर छठे स्थान पर है। किन्तु 70 फीसदी ऊर्जा जरूरतें अभी भी कोयले से पूरी की जा रही हैं। इसे लागतवार कम करने की जरूरत है। अत्यधिक बनावटी मरम्मत पैदा करने एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। पूरा मीडिया इसी काम में लगा रहता है। उत्पादन प्रक्रिया का फलसफा अमरीकी फलसफे पर आधारित होता जा रहा है, जिसमें 'यूज एंड थ्रो' का सिद्धांत सर्वोपरि है। पुराने समय में उत्पाद ऐसे होते थे जिनका मरम्मत करने सालों साल प्रयोग किया जा सकता था। मरम्मत करने वाले लोगों की एक बड़ी फौज को रोजगार भी मिलता था। अब तो ऐसे वस्तुएं बनने लगी हैं जिनको एक बार प्रयोग करने के फेंकना ही पड़ता है। इससे एक तो संसाधनों का अत्यधिक दोहन और खनन करना पड़ता है और दूसरे, इतना ज्यादा कचरा पैदा हो रहा है जिसके निपटारे की समस्या नियंत्रण से बाहर हो रही है। इस सबके लिए अतिरिक्त ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। टिकाऊ उत्पाद बनाने से इस फिजूलखर्ची से बचा जा सकता है।

दृष्टि

कोण

रक्षा निर्यात में ताकत बनकर उभरेगा भारत

पाकिस्तान

के केवल चार दिनों के बाद, हालाँकि मुसलिवराम ने इस आतंकवादी राष्ट्र को और अधिक नुकसान से बचा लिया है, लेकिन इस छोटी सी अवधि में पाकिस्तान को निश्चित रूप से भारी नुकसान हुआ होगा। पड़ोस और अगर हम सच को इन चार दिनों को देखें, तो भारत निश्चित रूप से अपनी रक्षा क्षमताओं, विशेष रूप से स्वदेशी रक्षा उपकरणों को वैश्विक स्तर पर अवशेष संबंधित श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ के बराबर या उससे भी बेहतर प्रदर्शित करने में सक्षम रहा। भारत सरकार के प्रेस सूचना ब्यूरो के अनुसार, 'ऑपरेशन सिंदूर' ने भारतीय प्रमाणितों द्वारा शत्रु को प्रौद्योगिकी को बेकार करने के ठोस सबूत भी पेश किए - चीनी पीएल-15 हथियार से हवा में मार करने वाली मिसाइलों, तुर्की मूल के यूपीवी, लंबी दूरी के रॉकेट, क्वाड्रिकॉप्टर और वाणिज्यिक ड्रोन के टुकड़े वरामद किए गए। पीछाअगे कहा है, 'जिनके बलात्कृतिका गया और उनको पीछाअगे को गई, जिससे पता चलता है कि पाकिस्तान द्वारा विदेशों से आपूर्ति किए गए उन्नत हथियारों को फायदा

उठान के प्रयासों के बावजूद, भारत का रवदेवों वायु रक्षा और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध नेटवर्क बेहतरीन बना हुआ है। गौरतलब है कि भारत का रक्षा निर्यात 2013-14 में 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 2023-24 में 21083 करोड़ रुपए हो गया, और 2024-25 में यह 23622 करोड़ रुपए हो गया। अगले वर्ष के लिए इसका लक्ष्य 35000 करोड़ रुपए के रक्षा उपकरण निर्यात करना है। श्रीलंक बाइटली, मालदीव, रूस, श्रीलंका, यूएई, फिलीपींस, सऊदी अरब, पोलैंड, मिस्र, इजरायल, स्पेन और चिली सहित 85 से अधिक देशों का रक्षा निर्यात करने हैं। भारत द्वारा निर्यात किए जाने वाले प्रमुख रक्षा उपकरणों में शामिल हैं- आकाश-सहस्र से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, जिसे अमेरिका जैसे देशों को निर्यात किया गया है और सूडान में प्रसारित किया गया। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जिसे फिलीपींस को निर्यात किया जा रहा है और अन्य दक्षिण-पूर्व

एशियाई देशों ने भी इसमें रुचि दिखाई है (सोवियत पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं)। पिनाका मट्टी-बैलर रॉकेट लांचर, जिसे आर्मेनिया को नियात किया गया, 155 मिमी ऑटो लॉरी गन, जिसे आर्मेनिया को नियात किया गया, जो उन्नत ऑटो लॉरी प्रणालियों में भारत की क्षमताओं को उजागर करता है। डोर्नियर-228 विमान, जिसे परिहहन और निगरानी भूमिकाओं के लिए विभिन्न देशों को नियात किया गया। हालाँकि, डेनू रक्षा वस्तुओं की विभिन्न देशों में पहले से ही मांग है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद परिदृश्य भारत के रक्षा नियात के पक्ष में और भी बदल गया है। भारत अब अधिक रक्षा सामान बेचने की बेहतर स्थिति में है। इस ऑपरेशन ने न केवल भारत की सैन्य साख को बढ़ाया है, बल्कि स्वदेशी रूप से विकसित रक्षा प्रणालियों की विश्वव्यापी प्रशंसा और भावगोशीता को जीवंत कर दिया भी किया है। कैसा रहा प्रदर्शन? पीएम नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि

औपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे मेड इन इंडिया हथियारों की प्रामाणिकता साबित हुई है। आज दुनिया देख रही है कि 21वीं सदी के युद्ध में मेड इन इंडिया रक्षा उपकरणों का समय आ गया है। भारत ने अपनी क्षमताओं का शानदार प्रदर्शन किया है और नए युग के युद्ध में अपनी श्रेष्ठता साबित की है। इसने भारत को स्वदेशी हथियारों और रक्षा प्रणालियों को कारगर बनाने में प्रशिक्षित करने का एक दुर्लभ अवसर प्रदान किया है। वास्तव में, हम युद्ध के मैदान में भारत के वर्तमान कार्य को दुनिया के भारत निर्मित हथियारों के प्रदर्शन को प्रशिक्षित करने वाला एक प्रचार अभ्यास कह सकते हैं, क्योंकि हम कह सकते हैं कि वे पक्षपात केवल मैदान में नहीं बल्कि वास्तव में और कुतूहल जैसी प्रमुख सैन्य शक्तियों द्वारा समर्थित बालकिक युद्ध जैसी स्थिति में सिद्ध हुए हैं। आकाश मिसाइल सिस्टम पर एक नौमिक दायित्व लिखता है कि भारत-पाकिस्तान तनाव के बीच, आकाश मिसाइल ने अपनी 'अग्नि परीक्षा' पास कर ली है। उल्लेखनीय है कि आकाश मिसाइल रक्षा प्रणाली भारत की स्वदेशी प्रणाली है, जिसने हाल ही में भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान अपनी प्रभावशालिता का प्रदर्शन किया है।



राजशाही समर्थकों का हौसला बढ़ाने पूर्व युवराज्ञी सड़कों पर उतरी

काठमांडू, 03 जून (एजेंसियां) ।

नेपाल में राजशाही की वापसी को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे अपने समर्थकों का हौसला बढ़ाने के लिए पूर्व युवराज्ञी हिमानी शाह भी सड़क पर आईं। अपने बेटे के साथ सड़क पर समर्थकों के बीच पहुंची हिमानी को देखकर लोगों में काफी उत्साह देख गया।

राजदरबार हत्याकांड की 24वीं बरसी पर दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। पहले यह आयोजन राजदरबार के भीतर ही करना था लेकिन सरकार ने राजपरिवार के सदस्यों को उसी राजदरबार में श्रद्धांजलि कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं दी जिस राजदरबार में रह कर शाह परिवार ने 240 वर्षों तक शासन चलाया था।

सरकार द्वारा राजदरबार में कार्यक्रम की अनुमति नहीं दिए जाने के बाद पूर्व युवराज्ञी हिमानी शाह ने काठमांडू के कमलादी में रहे गणेश मन्दिर में इसका आयोजन किया। सड़क

पर अपने समर्थकों के बीच गणेश मंदिर से एक बार फिर से राजशाही की वापसी के लिए संघर्ष का श्रीगणेश माना जा सकता है। वे हजारों समर्थकों के बीच शालीनतापूर्वक मुस्कुराते हुए सबका अभिवादन स्वीकार करती नजर आईं।

हिमानी का सड़क पर आना विपक्षी के उन सवालों का भी जवाब है जो यह कहते हैं कि जिस राजसंस्था की पुनर्बहाली के लिए उनके समर्थक सड़कों पर पुलिस की लाठियां खा रहे हैं उस राजसंस्था का कोई भी सदस्य कभी भी उनके साथ सड़क पर क्यों नहीं आता अपने

बीच राजपरिवार के सदस्यों को देख कर समर्थकों और आम जनता में काफी उत्साह देखा गया।

हिमानी शाह के सड़क पर आने के बाद सोमवार को एक दिन के लिए स्थगित संघर्ष को मंगलवार से फिर शुरू करने की घोषणा कर दी गई। राजसंस्था पुनर्बहाली के लिए बनाई गई जनसंघर्ष समिति ने मंगलवार से दोपहर को उसी स्थान पर प्रदर्शन करने की जानकारी दी है जो सरकार ने उपलब्ध कराया है। कल का प्रदर्शन काठमांडू के सफल मैदान में करने की जानकारी दी जाएगी।

न्यूज़ ब्रीफ

बिलावल भुट्टो ने जम्मू-कश्मीर विवाद को भारत से झगड़े की जड़ माना



न्यूयॉर्क। पाकिस्तान के पूर्व विदेशमंत्री और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के स्थायी समाधान के लिए जम्मू-कश्मीर विवाद का समाधान एक अनिवार्य शर्त है। नौ सदस्यीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे बिलावल ने चीन के एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में कहा कि मौजूदा संघर्ष विराम से स्थायी शांति आनी चाहिए। पाकिस्तान के दुनिया न्यूज टीवी चैनल ने एसोसिएट प्रेस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से यह खबर प्रसारित की है। बिलावल ने दोढ़क कहा कि जम्मू-कश्मीर विवाद को सुलझाए बिना कोई स्थायी समाधान संभव नहीं है। बिलावल ने कहा कि 1960 की सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का फैसला तनाव बढ़ाने वाला है। इस संबंध में उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से दोनों देशों के बीच बातचीत को सुविधाजनक बनाने में अपनी भूमिका निभाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जम्मू-कश्मीर, आईडब्ल्यूटी और आतंकवाद पर भारत के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। बिलावल भुट्टो के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद के हालात की जानकारी दी है।

दक्षिण कोरिया चुनेगा अपना अगला राष्ट्रपति, मतदान शुरू



सियोल। दक्षिण कोरिया के लोग अपना नया राष्ट्रपति चुनेंगे। राष्ट्रपति पद के लिए हो रहे उपचुनाव के लिए मतदान मंगलवार सुबह 6 बजे देशभर के 14,295 मतदान केंद्रों पर शुरू हो गया। यह उपचुनाव संवैधानिक न्यायालय के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को पिछले साल के अंत में मार्शल लॉ घोषित करने के कारण अप्रैल में पद से हटाए जाने के 60 दिन बाद हो रहा है। खबर के अनुसार, विजयी उम्मीदवार बुधवार को पदभार ग्रहण करेंगे। नए राष्ट्रपति का कार्यकाल जून 2030 तक रहेगा। मतदान रात 8 बजे समाप्त होगा। इसके लगभग 30 मिनट बाद 254 केंद्रों पर मतपत्रों की गिनती शुरू हो जाएगी। आधीरात बाद नतीजा आने की उम्मीद है। आंतरिक एवं सुरक्षा मंत्रालय के अनुसार, पात्र मतदाताओं की संख्या लगभग 44.39 मिलियन है। चुनाव से पहले युक्वा और शुक्वा को हुए प्रारंभिक मतदान में उदारवादी डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ कोरिया के उम्मीदवार ली जै-म्यांग को लगभग 49 प्रतिशत मत हासिल हुए हैं। रूढ़िवादी पीपल पावर पार्टी के उम्मीदवार किम मून-सू उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी हैं। प्रारंभिक मतदान में लगभग 15.42 मिलियन मतदाताओं ने हिस्सा लिया।

कोलोराडो हमला बाइडन की खुली सीमा नीति का परिणाम: ट्रंप

वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोलोराडो के बोल्डर शहर में इजराइल समर्थक रैली पर हुए



हिंसक हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे अमेरिका में बिन्दुल बदर्शत न करने योग्य करार दिया है। उन्होंने इस घटना को जो बाइडन की खुली सीमा नीति का परिणाम बताते हुए एक बार फिर कड़ी आब्रजन नीति और सीमाओं की सुरक्षा की मांग दोहराई। ट्रंप ने सोमवार को अपनी सोशल मीडिया साइट ट्रथ सोशल पर एक बयान जारी कर कहा कि कल कोलोराडो के बोल्डर में हुआ भयानक हमला अमेरिका में बदर्शत नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह घटना दर्शाती है कि देश की सीमाएं कमजोर हैं और राष्ट्रपति बाइडन की नीति के कारण अवैध और अमेरिका-विरोधी तत्व देश में घुसपैठ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप नीति के तहत उन्हें देश से निकाल बाहर करना होगा। आतंकवाद जैसे कृत्यों के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उल्लेखनीय है कि पैरल स्ट्रीट मॉल के पास हमला हुआ, जहां प्रो-इजराइल रैली चल रही थी। आरोपित ने कथित रूप से इसीनिडरी डिवाइस और घरेलू फ्लेमश्रोअर का उपयोग करते हुए हमला किया और फ्री फिलिस्तीन के नारे लगाए। जांच में पता चला है कि आरोपित मिस्र निवासी मोहम्मद सबरी सोलिमान (45 वर्ष) करीब एक साल से इस हमले की योजना बना रहा था। इस हमले में चार महिलाएं और चार पुरुष घायल हुए हैं। आरोपित कथित रूप से वीजा अवधि खत्म होने के बावजूद अमेरिका में अवैध रूप से रह रहा था।

पाकिस्तान की कराची जेल से 216 कैदी भागे

भूकंप के बाद मची थी अफरातफरी, 80 से ज्यादा दोबारा पकड़े गए



इस्लामाबाद, 03 जून (एजेंसियां) । पाकिस्तान के कराची शहर में सोमवार रात एक भूकंप के झटके के बाद मची अफरातफरी के बीच मलिर जेल से 216 कैदी फरार हो गए। इनमें से करीब 80 कैदियों को दोबारा पकड़ लिया गया है, जबकि 135 अब भी फरार हैं। घटना ने पाकिस्तान की जेल सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं जेल सुपरिंटेंडेंट अरशद शाह के मुताबिक, भूकंप के झटके महसूस होने पर 700 से 1000 कैदियों को ऐहतियातन बैकों से बाहर निकाला गया था। इसी दौरान मेन गेट पर भगदड़ मच गई और 216 कैदी मौका पाकर फरार हो गए। प्रारंभिक मीडिया रिपोर्ट्स में दीवार तोड़कर भागने की बात सामने आई थी, जिसे

प्रशासन ने खारिज किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी कैदी मुख्य द्वार से ही भीड़ का फायदा उठाकर भागे।फरार कैदियों की तलाश के लिए स्पेशल सिक्वोरिटी यूनिट (स्सू), रैपिड रिसपॉन्स फोर्स (क्रक्रन्स), रेंजर्स और फ्रंटियर कोर (स्सष्ट) की टीमें संयुक्त रूप से तलाशी अभियान चला रही हैं। जेल का नियंत्रण रेंजर्स और स्सष्ट ने तुरंत संभाल लिया था। इस भगदड़ के दौरान एक कैदी की मौत हो गई है, जबकि चार सुरक्षाकर्मी घायल हुए हैं। गृह मंत्री मुहम्मद जर्रर लांजार ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि प्रारंभिक जांच में प्रशासनिक लापरवाही की आशंका जताई जा रही है।

मुख्यमंत्री मुराद अली शाह को घटना की पूरी

जानकारी दी गई है। उन्होंने गृह मंत्री को तुरंत मौके पर पहुंचकर हालात की निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। सिंध के राज्यपाल कामरान टेसोरी ने भी घटना का संज्ञान लिया है और सभी फरार कैदियों की जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित करने को कहा है। गृह मंत्री ने आश्चर्य किया है कि हर फरार कैदी की पहचान और रिकॉर्ड प्रशासन के पास उपलब्ध है, और उनके घरों तथा संभावित ठिकानों पर छापेमारी जारी है। जेल मंत्री ने कहा है कि लापरवाह जेल अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, सुरक्षा चौकियों और निगरानी व्यवस्था को और कड़ा किया जा रहा है ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो सकें।

नूर खान एयरबेस पर अमेरिका का है कंट्रोल बिना इजाजत पाक अफसर भी नहीं जा सकते



वया पाकिस्तान का नूर खान एयरबेस अमेरिका की कस्टडी में है वया अमेरिका एयरबेस की मदद से इस रीजन में अपनी पकड़ को फिर से मजबूत कर रहा है यह दावा पाकिस्तानी पत्रकार और डिफेंस विशेषज्ञ ने किया है कि रावलपिंडी में स्थित नूर खान एयरबेस पर अमेरिका का नियंत्रण है और पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों को भी इस बेस पर जाने की इजाजत नहीं है। यह दावा इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पाकिस्तानी पत्रकार और डिफेंस विशेषज्ञ ने किया दावा, लोग उठा रहे सवाल पाक विशेषज्ञ ने कहा कि नूर खान एयरबेस पाकिस्तान वायुसेना का एक अहम केंद्र है, लेकिन अब ये अमेरिकी सेना के अधीन है इस बेस पर बार-बार अमेरिकी विमानों को देखा गया, लेकिन उनके कार्यों की जानकारी पारदर्शी नहीं है। यह बेस बेनजीर भुट्टो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और पीएफए कॉलेज चकलाला का हिस्सा है। नूर खान एयरबेस रावलपिंडी में पाकिस्तान के सैन्य मुख्यालय के पास स्थित है और इसे पाकिस्तान की हवाई गतिविधियों का केंद्र माना जाता है। विशेषज्ञ ने अपने बयान में संकेत दिया कि अमेरिकी सेना की मौजूदगी के कारण पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों को इस बेस के संचालन में कोई भूमिका नहीं दी जा रही है।

पाक में दो पुलिस थानों पर आतंकी हमला, सात बलूच लड़के मारे गए

इस्लामाबाद, 03 जून (एजेंसियां) ।

पाकिस्तान के दो प्रांतों में पिछले 24 घंटे के दौरान दो पुलिस थानों पर बड़ा हमला हुआ। इस हमले से इतर मुठभेड़ में सात बलूच लड़के मारे गए। बलूच लड़कों को पाकिस्तान आतंकी बता रहा है। बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रहे हैं। वहां लंबे समय से आजादी के लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं।

खबर के अनुसार, खैबर पखूनख्वा प्रांत के बाजौर जिला और बन्नु जिले में दो पुलिस स्टेशनों पर आतंकवादियों के हमले को विफल कर दिया गया। खैबर पखूनख्वा के पुलिस महानिरीक्षक जुल्फिकार हमीद ने कहा कि लोई मामुंड (बाजौर जिला) और मिरयान (बन्नु) में पुलिस स्टेशनों पर देररात आतंकवादियों ने हमला किया। पुलिस बल ने बहादुरी से हमलावरों का सामना किया और उन्हें खदेड़ दिया। हमीद ने पुलिस बल के लिए प्रशंसा पत्र और पुरस्कार की घोषणा की है। इसके अलावा सुरक्षा बलों ने बलूचिस्तान में दो अलग-अलग अभियानों में सात बलूच लड़कों को मार गिराया।



सेना की मीडिया विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (आईएसपीआर) ने मंगलवार को प्रेस विज्ञप्ति में यह जानकारी दी। विज्ञप्ति में कहा गया कि मरने वाले सातों आतंकवादी हैं। यह अभियान दो जून को चलाया गया। कच्छी जिले के माच के सामान्य क्षेत्र में खुफिया आधारित ऑपरेशन के दौरान पांच आतंकवादियों को मार गिराया गया। कलात जिले के मार्गड के सामान्य क्षेत्र में दो आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। पाकिस्तान की सेना ने कहा कि मारे गए सातों आतंकी फितना अल हिंदुस्तान के हैं। उल्लेखनीय है कि आतंकवाद

परस्त पाकिस्तान लंबे समय से बलूचिस्तान के विद्रोहियों को फितना अल हिंदुस्तान (विद्रोही और हिन्दुस्तान के एजेंट) कहकर इस राजनीतिक समस्या को धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहा है। साथ ही टीटीपी को भी 'फितना अल खवारिज' कहकर (धार्मिक अपशब्द) भारत का साथ देने वाला बताकर प्रलाप करता रहता है। सैन्य अधिकारी भी हुकूमत की हां में हां मिलाते हैं। डीजी आईएसपीआर लिफ्टनंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि बलूचिस्तान को कभी भी पाकिस्तान से अलग नहीं होने दिया जाएगा।

तुर्की में शांति वार्ता के लिए ट्रंप तैयार, पुतिन और जेलेंस्की से मुलाकात को लेकर व्हाइट हाउस का बयान

वॉशिंगटन, 03 मई (एजेंसियां) ।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयप एर्दोआन के उस प्रस्ताव के लिए तैयार हैं, जिसमें उन्होंने ट्रंप, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के बीच तीन-तरफा शांति वार्ता आयोजित करने की पेशकश की है। यह जानकारी सोमवार को व्हाइट हाउस की ओर से दी गई। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने सोमवार को कहा कि उनका देश रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए इस उच्चस्तरीय वार्ता की मेजबानी करने को तैयार है। उन्होंने कहा, तुर्की इस प्रकार की बैठक के लिए आवश्यक कदम उठाने को तैयार है। इस प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया देते हुए व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लिच्विट ने कहा, राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि यदि ऐसी स्थिति आती है, तो वे इसके लिए तैयार हैं। लेकिन वे चाहते हैं कि दोनों नेता और दोनों पक्ष एक साथ बातचीत की मेज पर आएँ। यह बयान



ऐसे समय आया है जब रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में कूटनीतिक समाधान की संभावनाएँ सीमित होती दिख रही हैं। एर्दोआन इससे पहले भी रूस-यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए

मध्यस्थता की कोशिशें करते रहे हैं। हालाँकि, अभी तक इस प्रस्ताव पर पुतिन या जेलेंस्की की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

यूएस संसद में भारत का गुणगान: महात्मा गांधी के बाद पीएम मोदी को बताया सबसे महान नेता

वॉशिंगटन। दुनिया के कई देश भारत की तारीफ कर चुके हैं। यहां आयोजित अमेरिका भारत रणनीतिक साझेदारी संघ के दौरान अमेरिकी प्रतिनिधियों ने जिस तरह से भारत की तारीफ की, उसे देखते हुए ऐसा लग रहा है कि व्यापार के मामले में भारत और अमेरिका एक अच्छी साझेदारी निभाने वाले हैं। यहां मौजूद अमेरिकी सांसद और इंडिया कॉकस के सह-अध्यक्ष रिच मैककॉर्मिक ने दिल खोलकर भारत और पीएम मोदी की तारीफ की। अमेरिकी सांसद रिच मैककॉर्मिक ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ में कहा है कि वे भारत के सबसे प्रभावशाली राजनेता हैं। वे शायद भारत में महात्मा गांधी के बाद सबसे महान नेता हैं। उन्होंने आगे कहा कि पीएम बेदद विनम्र हैं और जो लोग उन्हें प्रधानमंत्री बनने से पहले जानते थे, वे बताते हैं कि मोदी उनके घर आने पर फर्श पर सोते थे। उन्होंने पीएम मोदी को जननेता बताते हुए कहा - वे आक्रामक और राष्ट्रवादी प्रतीत हो सकते हैं, लेकिन उन्हें अर्थव्यवस्था को विकसित करने का वैश्विक दृष्टिकोण अच्छी तरह समझ है। आने वाला समय भारत का है और इस बात को अब अमेरिकी राजनेता भी मान रहे हैं। तभी तो यूएस-इंडिया स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप फोरम में अमेरिकी प्रतिनिधियों ने भारत की तारीफ करते हुए इसकी तुलना चीन से कर दी अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनक ने पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा नेता कहा, जिसे पूरे देश से समर्थन मिला है। अमेरिकी सीनेटर स्टीव डेन्स ने भारत की तुलना चीन से करते हुए कहा कि वैश्विक स्तर पर निवेश अब चीन से हटकर भारत की ओर बढ़ रहा है।



पीयूष गोयल ने सिंगापुर के साथ भारतीय शिपिंग क्षेत्र में अवसरों पर चर्चा की

नई दिल्ली, 03 जून (एजेंसियां) ।

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गायल ने मंगलवार को सिंगापुर के उप-प्रधानमंत्री गान किम योंग के साथ मुलाकात की। उन्होंने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने तथा भारतीय शिपिंग क्षेत्र में व्यापक अवसरों पर चर्चा की। इस दौरान द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ाने पर चर्चा की गई। इसके साथ ही उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों, विशेष रूप से शिपिंग क्षेत्र में भारत की ओर से प्रदान किए जाने वाले जबरदस्त अवसरों पर

प्रकाश डाला।

इससे पहले गोयल ने तीन दिवसीय फ्रांस की आधिकारिक यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए फ्रांसीसी नेताओं और कारोबारियों से मुलाकात की थी। वाणिज्य मंत्री ने देर रात पेरिस में शीर्ष फ्रांसीसी मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें कीं। इसके अलावा गोयल ने अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) के कार्यकारी निदेशक के डॉ. फतिह

बिरोल से भी मुलाकात की। वाणिज्य मंत्री ने अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के ईडी फतिह बिरोल, नाइजीरिया के व्यापार मंत्री जुमोके ओडुवोले, फ्रांस के अर्थव्यवस्था और वित्त मंत्री एरिक लोम्बाई, ऑटोमोटिव आपूर्तिकर्ता कंपनी वेलियो ग्रुप के सीईओ क्रिस्टोफ पेरिलाट और लोरियल ग्रुप के सीईओ निकोलस हिरोनिमस सहित शीर्ष सीईओ और मंत्रियों के साथ कई बैठकें की हैं और भारत में निवेश के विशाल अवसरों पर प्रकाश डाला है। पेरिस में हुई बैठक में

अक्षय ऊर्जा, ऑटोमोबाइल विनिर्माण, इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) और उपभोक्ता उत्पादों जैसे प्रमुख क्षेत्रों में भारत के विकास के लिए नए अवसरों का पता लगाया गया। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) के कार्यकारी निदेशक के डॉ. फतिह बिरोल से भी मुलाकात की। उन्होंने बताया कि बिरोल से मिलकर खुशी हुई। इस दौरान समग्र वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य और भारत और आईईए के बीच गहरी होती साझेदारी पर अच्छी चर्चा हुई।

न्यूज़ ब्रीफ

प्रोस्टार्म इन्फो सिस्टम्स का शेयर 19 प्रतिशत बढ़त के साथ सूचीबद्ध



नई दिल्ली। एकीकृत बिजली समाधान कंपनी प्रोस्टार्म इन्फो सिस्टम्स लिमिटेड के शेयर ने मंगलवार को अपने निर्गम मूल्य 105 रुपये से 19 प्रतिशत की बढ़त के साथ बीएसई और एनएसई पर सूचीबद्ध हो गया है। बीएसई पर शेयर का मूल्य 19 प्रतिशत चढ़कर 125 रुपये पर आया, जो बाद में 23.80 प्रतिशत की बढ़त के साथ 130 रुपये पर पहुंच गया। एनएसई पर भी समान रूप से शेयर ने 14.28 प्रतिशत की बढ़त के साथ 120 रुपये पर शुरुआत की। कंपनी ने 168 करोड़ रुपये के इस आईपीओ के लिए 95-105 रुपये प्रति शेयर का मूल्य दायरा तय किया था। आईपीओ से हासिल धन का उपयोग कंपनी ने 72.50 करोड़ रुपये के लिए पूंजीगत जरूरतों के लिए, 17.95 करोड़ रुपये के कर्ज भुगतान के लिए और शेष की अमाउंट को अन्य रणनीतिक कार्यों में निवेश करने के लिए किया है।

ईकस ने आईपीओ के लिए जमा किए दस्तावेज



नई दिल्ली। ईकस नामक विनिर्माण कंपनी ने एक गोपनीय मार्ग चुनकर भारतीय बाजार नियामक सेबी के समक्ष अपने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के लिए प्राथमिक दस्तावेज दाखिल किए हैं। यह विनिर्माण कंपनी करीब 20 करोड़ डॉलर जुटाने का लक्ष्य रख रही है। इस आईपीओ में कंपनी ने कई बिक्री पेशकश (ओएफएस) घटक को शामिल नहीं किया है। ईकस कंपनी ने मंगलवार को एक सार्वजनिक घोषणा में बताया कि उन्होंने सेबी और शेयर बाजारों के सामक्ष गोपनीय मार्ग के जरिये आईपीओ के लिए दस्तावेज दाखिल किए हैं। इस आईपीओ में कंपनी ने पूरी तरह से नए निर्गम पर आधारित है। ईकस कंपनी की इस कदम से उम्मीद है कि वे विशेष उत्पादों और सेवाओं के साथ उद्योग में अपनी जगह बना सकेंगे।

पिछले महीने 12,327 लोगों ने 5 लाख 70 हजार में खरीद डाली 7-सीटर कार



नई दिल्ली। 7-सीटर कारों की मांग लगातार बढ़ रही है लेकिन, महंगी होने के कारण कई लोग नहीं खरीद पाते हैं। इस समस्या का समाधान मारुति सुजुकी ने किया है। यही वजह है कि पिछले माह मई में मारुति सुजुकी की ईको 7 सीटर कार 12 हजार 3 सौ 27 लोगों ने 5 लाख 70 हजार में खरीद डाली। इससे मारुति सुजुकी इंडिया एक बार फिर गाड़ी बेचने में माहिर में देश की नंबर-1 कंपनी बनकर सामने आई है। मारुति ने पिछले महीने यानी मई में कुल 180,077 गाड़ियां बेचीं। जबकि मई 2024 में उसने 174,551 गाड़ियां बेची थीं। यानी सालाना आधार पर कंपनी को 3 प्रतिशत की ग्रोथ मिली। कंपनी की सेल्स में वैन सेगमेंट की ईको का अहम रोल रहा। ये देश की सबसे सस्ती 7-सीटर कार भी है। पिछले महीने इसकी 12,327 यूनिट बिकी। जबकि सालभर पहले ये आंकड़ा 10,960 यूनिट का था। इस यूटिलिटी वैन को 5, 6 और 7 सीटर फॉर्मेट में खरीद सकते हैं। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5.70 लाख रुपए है। मारुति ईको की सेल्स की बात करते तो ये हर महीने शानदार प्रदर्शन कर रही है। वहीं, मई में पिछले 7 महीने का सबसे शानदार प्रदर्शन किया है। नवंबर 2024 में इसकी 10,589 यूनिट, दिसंबर 2024 में इसकी 11,678 यूनिट, जनवरी 2025 में इसकी 11,250 यूनिट, फरवरी 2025 में इसकी 11,493 यूनिट, मार्च 2025 में इसकी 10,409 यूनिट, अप्रैल 2025 में इसकी 11,438 यूनिट और मई 2025 में इसकी 12,327 यूनिट बिकी। ईको में 11 सेप्टी कीवर्स मिलते हैं, जो सेप्टी से जुड़े सभी मौजूदा और कुछ आने वाले नियमों को पूरा करती हैं। इनमें रिवर्स पार्किंग सेंसर, डीजन इमोबिलाइज़र, दरवाजों के लिए चाइल्ड लॉक, सीट बेल्ट रिमाइंडर, इंटीडी के साथ एबीएस, 6 एयरबैग शामिल हैं। ईको को अब एक नया स्टीयरिंग व्हील और एक डिजिटल इंस्ट्रुमेंट क्लस्टर मिलता है। दोनों यूनिट कंपनी ने अपनी एस-प्रो और सेलेरियो से ली हैं।

ग्लोबल मार्केट से मिले-जुले संकेत एशियाई बाजार में खरीदारी का रुख

नई दिल्ली, 03 जून (एजेंसियां) ।

ग्लोबल मार्केट से मिले-जुले संकेत मिल रहे हैं। अमेरिकी बाजार पिछले सत्र के दौरान मजबूती के साथ बंद होने में सफल रहे। हालांकि डाउ जॉन्स प्यूचर्स गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। यूरोपीय बाजार पिछले सत्र के दौरान मिले-जुले परिणाम के साथ बंद हुए। वहीं एशियाई बाजारों में आमतौर पर तेजी का माहौल बना हुआ है।

अमेरिकी बाजार में पिछले सत्र के दौरान निचले स्तर से अच्छी खरीदारी हुई, जिसके कारण वॉल स्ट्रीट के सूचकांक मजबूती के साथ बंद होने में सफल रहे। एसएंडपी 500 इंडेक्स 0.41 प्रतिशत की मजबूती के साथ 5,935.94 अंक के स्तर पर बंद हुआ। इसी तरह नैस्डेक ने 128.85 अंक यानी 0.67 प्रतिशत उछल कर 19,242.61 अंक के स्तर पर पिछले सत्र के कारोबार का अंत किया। वहीं डाउ जॉन्स प्यूचर्स फिलहाल 126.28 अंक यानी 0.30 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 42,179.20 अंक के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है।

यूरोपीय बाजार पिछले सत्र के दौरान दबाव में कारोबार करने के बाद मिले-जुले परिणाम के साथ बंद हुए। एफटीएसई इंडेक्स 0.02 प्रतिशत की मामूली तेजी के साथ 8,774.26 अंक के स्तर पर बंद हुआ। दूसरी ओर, सीएसई इंडेक्स ने 0.19 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 7,737.20 अंक के स्तर पर पिछले सत्र के कारोबार का अंत किया। इसी तरह डीएक्स इंडेक्स 0.28 प्रतिशत फिसल कर 23,930.67 अंक के स्तर पर बंद हुआ।

एशियाई बाजार में आमतौर पर खरीदारी का माहौल बना हुआ है। एशिया के नौ बाजारों में से पांच के सूचकांक बढ़त के साथ हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं, जबकि दो सूचकांक गिरावट के साथ लाल निशान में बने हुए हैं। दक्षिण कोरिया और थाईलैंड के स्टॉक एक्सचेंज में छुट्टी होने की वजह से कोम्सी इंडेक्स और सेट कंपोजिट इंडेक्स में कोई हलचल नहीं है। एशियाई बाजारों में गिफ्ट निफ्टी फिलहाल 0.21 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 24,717.50 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.09 प्रतिशत टूट कर 3,887.04 अंक के स्तर पर आ गया है।



टोरेंट पावर ने बीपी सिंगापुर से बिक्री समझौते पर किए हस्ताक्षर

अहमदाबाद। टोरेंट पावर लिमिटेड (टीपीएल) ने वैश्विक एकीकृत ऊर्जा कंपनी बीपी की सहायक कंपनी बीपी सिंगापुर पीटीई लिमिटेड से 2027 से 2036 तक 0.41 एमएमटीपीए तक एलएनजी की आपूर्ति के लिए दीर्घकालिक खरीद और बिक्री समझौते (एसपीए) पर हस्ताक्षर किए हैं। टीपीएल की ओर से बताया गया कि इस समझौते के तहत टीपीएल द्वारा खरीदी गई एलएनजी का देश की बढ़ती बिजली की मांग को पूरा करने के लिए



रणनीतिक रूप से उपयोग किया जाएगा। साथ ही पीक डिमांड अवधि में पूर्ण पावर सप्लाई करने और नवीकरणीय ऊर्जा को संतुलित करने के लिए 2,730 मेगावाट के संयुक्त चक गैस-फायर पावर प्लांट (जीबीपीपी) का संचालन भी टीपीएल द्वारा किया जाएगा। यह समझौता टोरेंट ग्रुप की सिटी गैस इस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) इकाई - टोरेंट गैस लिमिटेड (टीजीएल) को एलपीजी की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद करेगा, जिससे कंपनी की घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक ग्राहकों के साथ-साथ सीएनजी वाहनों को गैस की आपूर्ति सुनिश्चित कर पाएगी।

ओर, निकर्केई इंडेक्स 104.23 अंक यानी 0.28 प्रतिशत की तेजी के साथ 37,574.90 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.48 प्रतिशत उछलकर 3,363.48 अंक के स्तर पर पहुंच गया है। हैंग सेंग इंडेक्स ने मजबूत छलांग लगाई है। फिलहाल यह सूचकांक 252.73 अंक यानी 1.09

प्रतिशत की मजबूती के साथ 23,410.70 अंक के स्तर पर पहुंचा हुआ है। इसी तरह ताइवान टैडेक्स 161.23 अंक यानी 0.77 प्रतिशत की बढ़त के साथ 21,163.94 अंक के स्तर पर और जकार्ता कंपोजिट इंडेक्स 0.08 प्रतिशत की मामूली तेजी के साथ 7,070.51 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहे हैं।

पूर्वोत्तर में पहला क्षेत्रीय परिसर स्थापित करेगा आईआईसीए कॉर्पोरेट प्रशासन और विकास को आगे बढ़ाएगा

नई दिल्ली, 03 जून (एजेंसियां) ।

समावेशी राष्ट्रीय विकास और क्षेत्रीय क्षमता निर्माण की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए पूर्वोत्तर में कॉर्पोरेट प्रशासन उत्कृष्टता और सतत विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय कॉर्पोरेट मामले संस्थान (आईआईसीए) ने क्षेत्र में अपना पहला क्षेत्रीय परिसर स्थापित करने की घोषणा की है। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने मंगलवार को जारी बयान में बताया कि कॉर्पोरेट प्रबंधन और विकास को बढ़ावा देते हुए आईआईसीए पूर्वोत्तर में पहला क्षेत्रीय परिसर खोलेगा। आईआईसीए शिलांग परिसर प्रमुख क्षेत्रों में विशेष प्रशिक्षण, अनुसंधान और नीति सलाह के लिए क्षेत्रीय केंद्र के रूप में काम करेगा। इसमें प्रधानमंत्री पूर्वोत्तर विकास पहल (पीएम-डेवआईएनई) के तहत निवेश होगा।

मंत्रालय के मुताबिक प्रधानमंत्री की पूर्वोत्तर विकास पहल (पीएम-डेविन) के तहत 100.95 करोड़ रुपये के निवेश से समर्थित, शिलांग परिसर प्रमुख क्षेत्रों में विशेष प्रशिक्षण, अनुसंधान और नीति सलाह के लिए एक क्षेत्रीय केंद्र के रूप में काम करेगा। आईआईसीए ने अपने पहले क्षेत्रीय परिसर के लिए मेगालय के न्यू शिलांग टाउनशिप में पांच एकड़ भूमि का औपचारिक अधिग्रहण किया है। भूमि हस्तांतरण और अधिग्रहण का कार्य मेगालय



सरकार की ओर से योजना विभाग के संयुक्त सचिव के. हिनीवता और भारत सरकार की ओर से उप-सचिव शंखर श्रीवास्तव ने किया। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने बताया कि भूमि हस्तांतरण समारोह की अध्यक्षता मेगालय सरकार के मुख्य सचिव डोनाल्ड फिलिप्स वाइलिंग और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की सचिव दीप्ति गौर मुखर्जी

ने की। इस अवसर पर आईआईसीए के महानिदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) ज्ञानेश्वर कुमार सिंह, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव इंद्रदीप सिंह धारोवाल, योजना विभाग के आयुक्त और सचिव सीवीडी डिपेंद्रादोह, आईआईसीए के (कनल) अमनदीप सिंह पुरी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।

मादक पदार्थ का नेटवर्क खत्म करने के लिए एआई-संचालित तरीका अपनाए डीआरआई: सीतारमण

नई दिल्ली, 03 जून (एजेंसियां) ।

केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को राजस्व सुफिकिया निदेशालय (डीआरआई) से तस्करी, मादक पदार्थों और अवैध व्यापार से निपटने के लिए एक समग्र और प्रौद्योगिकी-संचालित दृष्टिकोण अपनाने की अपील की। सीतारमण ने कहा कि एजेंसियों को वैश्विक व्यापार और सुरक्षा खतरों की बढ़ती जटिलता के अनुरूप विकसित होना चाहिए।

सीतारमण ने राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के वसंत कुंज क्षेत्र स्थित केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के तहत डीआरआई के नए मुख्यालय भवन के उद्घाटन के



अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए यह बात कही। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रवर्तन एजेंसियों को वैश्विक व्यापार और सुरक्षा खतरों की बढ़ती जटिलता के अनुरूप विकसित होना चाहिए। इसके दृश्यमान और अंतिम परिणाम सामने आने चाहिए। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के शब्दों को दोहराते हुए कहा कि सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन - यही वह भावना है जिसके साथ हमें आगे बढ़ते रहना है। वित्त मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि डीआरआई उन चुनिंदा भारतीय एजेंसियों में से एक है जो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र की रक्षा करती है। हम सोना के बारे में जितना बोले हैं, नारकोटिक्स सबसे बड़ा खतरा है जो हर राज्य और यहां तक कि छोटे शहरों में भी घुसपैठ कर चुका है। स्थल और कॉलेज इसके पहले शिकार हैं। डीआरआई को इसे रोकना होगा और फिर राज्य पुलिस के साथ समन्वय करना होगा। हमें खतरों के आकार और दायरे के बारे में बेहतर समन्वय और बेहतर समझ की आवश्यकता है।

उन्होंने प्रवर्तन अधिकारियों से कहा, बड़ी तस्करी को ध्यान में रखते हुए समग्र रूप से जांच करें। आपको गहरे प्रणालीगत जोखिमों और खतरों को उजागर करने के लिए अव्यक्त बिंदुओं को जोड़ना होगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि तस्करी के पूरे नेटवर्क को खत्म करना ही किसी भी जांच का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। उन्होंने कहा कि केवल छोटी-छोटी जमानियां या गिरफ्तारियां तक ही सीमित न रहें। वित्त मंत्री ने कहा, अगर आप छोटी मछलियों को पकड़ते हैं तो यह अच्छा नहीं है। बड़ी तस्करी श्रृंखला का पता लगाना होगा और उस पर कार्रवाई करनी होगी। ठीक नतीजे सामने आएँ और उन्हें तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचाया जाए। इससे पहले निर्मला सीतारमण ने वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के साथ डीआरआई मुख्यालय के नए भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राजस्व सचिव अरविंद्र श्रीवास्तव, सीबीआईसी के अध्यक्ष संजय अग्रवाल और वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।



डी. गुकेश ने नॉर्वे शतरंज के 7वें राउंड में अर्जुन एरिगैसी को हराकर दूसरी जीत दर्ज की

स्टावेंगर, 03 जून (एजेंसियां)। नॉर्वे शतरंज 2025 के सातवें राउंड में सभी बोर्ड्स पर रोमांचक मुकाबले देखने को मिले। इस दौर की सबसे चर्चित मिड़त मौजूदा विश्व चैम्पियन डी गुकेश और भारत के ही वैंडमास्टर अर्जुन एरिगैसी के बीच हुई।

दोनों खिलाड़ियों के बीच तेज़ मुकाबला हुआ, जहां गुकेश ने धैर्य बनाए रखते हुए कड़ी मेहनत के बाद इस टूर्नामेंट में दूसरी जीत हासिल की। इससे पहले छठे राउंड में डी गुकेश ने और वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन के बीच मुकाबले में शानदार जीत दर्ज की थी। अर्जुन ने ओपनिंग में शानदार शुरुआत करते हुए तेज़ आक्रामक चालों से गुकेश पर दबाव बनाया, लेकिन गुकेश ने जबरदस्त डिफेंसिव कौशल दिखाते हुए खेल को जटिल एंडगेम तक पहुंचाया। समय की कमी में दोनों खिलाड़ियों के बीच तेज़ मुकाबला हुआ, जहां

गुकेश ने धैर्य बनाए रखते हुए कड़ी मेहनत के बाद जीत हासिल की। अमेरिकी ग्रैंडमास्टर फबियानो कारुआना ने चीनी ग्रैंडमास्टर और बर्थडे बॉय वे यी के खिलाफ शुरुआती बहुत बड़ा और लंबे एंडगेम में शानदार जीत दर्ज की। दिन का आखिरी मुकाबला विश्व नंबर 1 मैग्नस कार्लसन और हिकारु नाकामुरा के बीच खेला गया, जो क्लासिकल गेम में जल्दी ड्रा हो गया। हालांकि, अर्मागेंडन गेम में कार्लसन ने जीत दर्ज कर अतिरिक्त अंक हासिल किए।

नॉर्वे विमेंस शतरंज: जु वेनजुन टॉप पर
विश्व महिला शतरंज चैम्पियन जु वेनजुन ने सारा खादेम के खिलाफ क्लासिकल गेम में शानदार एंडगेम खेलते हुए जीत दर्ज की। दिन की दूसरी क्लासिकल जीत चीन की तिंगजी लेई को मिली, जिन्होंने वाइट पोसेज से भारत की वैशाली रमेशबाबू को मात दी। भारत की हम्पी कोनेरु और अन्ना मुश्चिुक के बीच मुकाबला शांति से ड्रा रहा, जिसमें काफी पीस एक्सचेंज हुए।

न्यूज़ ब्रीफ

पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतने पर महिला कांस्टेबल पुष्पा चाहर सम्मानित



मुरादाबाद। मुरादाबाद पुलिस लाइन में तैनात महिला कांस्टेबल पुष्पा चाहर पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 410 किलोग्राम भार उठाकर अबल आने पर आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पुलिस अधिकारियों के साथ सम्मानित किया। पुष्पा चाहर ने बदायूं में आयोजित बदायूं में आयोजित पावर लिफ्टिंग में 410 किलोग्राम भार उठाकर प्रथम स्थान हासिल कर गोल्ड मेडल जीता। इसके अलावा उन्होंने मेरठ में भी पावर लिफ्टिंग में गोल्ड जीता है। पुष्पा चाहर ने स्ट्रांग वूमन का खिलाफ भी जीता। सोमवार को एसएसपी सतपाल अतिल ने उन्हें अपने दफ्तर में सम्मानित किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक देहात कुवर आकाश सिंह, सदर कोतवाली की क्षेत्राधिकारी सुनीता देहिया भी मौजूद रही।

नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 टूर्नामेंट अब 5 जुलाई को बेंगलुरु में



नई दिल्ली। नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 प्रतियोगिता का आयोजन अब 5 जुलाई को बेंगलुरु के श्री कांतारवा स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। पहले यह इवेंट 24 मई को होना तय था, लेकिन सुरक्षा कारणों और देश के प्रति एकजुटता के भाव के चलते इसे पुनः निर्धारित किया गया है। जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स ने मंगलवार को जानकारी दी कि यह भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय भाला फेंक टूर्नामेंट होगा, जो नीरज चोपड़ा, जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एएफआई) और वर्ल्ड एथलेटिक्स (डब्ल्यूए) के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। यह भारत में अब तक का सबसे उच्च स्तर का अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक्स मुकाबला होगा। प्रतियोगिता की अगुवाई ओलंपिक चैंपियन और मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन नीरज चोपड़ा करेंगे। नीरज चोपड़ा क्लासिक टूर्नामेंट का उद्देश्य दुनिया भर की शीर्ष प्रतिभाओं को भारत में लाना और देश के नए एथलीट्स को प्रेरणा देना है। उनके साथ भाला फेंक की दुनिया के ये दिग्गज भी मैदान में उतरेंगे। एंडरसन पीटर्स (ग्रेंनेडा) – दो बार के वर्ल्ड चैंपियन, थॉमस रोहवर (जर्मनी) – रियो 2016 ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, जूलियस येगो (केन्या) – 2015 के वर्ल्ड चैंपियन, किशोर जेना – एशियन गेम्स के रजत पदक विजेता और भारत के उभरते सितारे।

केन विलियमसन ने फिर से न्यूजीलैंड क्रिकेट का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दफ्तार



वेलिंग्टन। पूर्व कप्तान केन विलियमसन ने फिर से न्यूजीलैंड क्रिकेट का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दफ्तार दिया है और संभावना है कि वे अगले महीने जिम्बाब्वे के खिलाफ होने वाली दो मैचों की टैस्ट सीरीज में नहीं खेलेंगे। विलियमसन ने पिछले साल भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट स्वीकार नहीं किया था ताकि वे दुनिया भर में टी20 और अन्य लीग में खेलने के लिए स्वतंत्र रहें। इसके बजाय उन्होंने पिछले साल एक केजुअल कॉन्ट्रैक्ट किया था और 2024 में न्यूजीलैंड के 13 टैस्ट में से नौ में खेलते हुए 1,000 से ज्यादा रन बनाए। न्यूजीलैंड क्रिकेट की ओर से मंगलवार को जारी 20 खिलाड़ियों की कॉन्ट्रैक्ट सूची में विलियमसन का नाम नहीं था। इसके साथ ही डेवीन कोर्नेल, फिन एलन, टिम सिफर्ट और लॉक फर्ग्यूसन भी शामिल नहीं थे क्योंकि वे खिलाड़ी भी विदेशी टी20 लीग में हिस्सा ले रहे हैं। विलियमसन के फिर से केजुअल कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने की संभावना है। टिम साउथी के रिटायर होने के बाद आलराउंडर मोहम्मद अब्बास और जेक फोल्क्स, विकेटकीपर मिच हे और स्पिनर आदि अशोक को पहली बार सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इसके अलावा ईश सोदी, एजाज पटेल और जोश क्लार्कसन भी टीम में शामिल हैं। विलियमसन फिनाल इंग्लिश काउंटी चैम्पियनशिप और टी20 ब्लास्ट में मिडलसेक्स के लिए खेल रहे हैं और द हंड्रेड में लंदन स्पिरिट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जुलाई के अंत और अगस्त की शुरुआत में न्यूजीलैंड के जिम्बाब्वे दौरे के दौरान उनकी काउंटी प्रतिबद्धताएं जारी रहने की संभावना है। लंदन में पिछले महीने एक प्रेस

18 साल का इंतजार खत्म, पंजाब को रौंदकर आरसीबी बनी नई चैंपियन

अहमदाबाद, 03 जून (एजेंसियां)। 18 साल का इंतजार खत्म हुआ और 18 नंबर की जर्सी वाले विराट कोहली का सपना आखिरकार पूरा हुआ। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को रौंदकर अपने करोड़ों चाहने वालों बड़ा गिफ्ट दे दिया। खिताबी मुकाबले में विराट कोहली की टीम ने 190 रन बनाए थे, जबकि पंजाब की टीम अच्छी शुरुआत के बावजूद लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकी। वह जीत से सिर्फ 6 रन दूर रह गई, जबकि शशांक सिंह की 30 गेंदों में 3 चौके और 6 छक्के की मदद से खेली गई नाबाद 61 रनों की पारी बेकार गई। जीत की सुगंध तभी मिल गई थी जब श्रेयस अय्यर एक रन पर आउट हुए। उस समय विराट का आक्रामक जश्र पूरी कहानी बयां कर रहा था। जब आखिरी ओवर में लगा कि अब जीत से कोई रोक नहीं सकता तो विराट कोहली की आंखों में आंसू थे। वह रो पड़े थे। भावनाओं का गुबार रोकते नहीं रुक रहा था। दूसरी ओर, पंजाब के चाहने वाले निराशा में डूब चुके थे।

पंजाब किंग्स की पारी का रोमांच
191 रनों के पहाड़ सरीखे लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब किंग्स की टीम को अनकैप्ड प्रियांश आर्य और प्रभसिमरन सिंह ने अच्छी शुरुआत दी। इन दोनों ने पहले विकेट के लिए 5 ओवरों में 43 रन जोड़े। इसी स्कोर पर प्रियांश को जोश हेजलवुड ने अपनी रणनीति के अनुसार की गई गेंद पर शिकार बनाया। डीप स्केयर लेग बाउंड्री पर फिल साल्ट ने कमाल का कैच लपका।



उन्होंने पहले गेंद को पकड़ा, लेकिन जब बाउंड्री से बाहर जाने लगे तो गेंद को अंदर की ओर उछालकर वापस लपक लिया। इस तरह से प्रियांश आर्य की पारी 24 रनों पर खत्म हो गई। उन्होंने 19 गेंदों का सामना किया, जबकि 4 चौके लगाए।
श्रेयस अय्यर का बल्ला दे गया धोखा
प्रभसिमरन सिंह 26 रन पर चलते बने। उन्हें कुणाल पंड्या ने पवेलियन भेजा। इसके बाद कप्तान श्रेयस अय्यर को रोमारियो शेफर्ड ने जितेश शर्मा के हाथों सिर्फ एक रन पर कैच कराया तो पूरे स्टेडियम में फैले आरसीबी के चाहने वाले

सपना पूरा हुआ तो राने लगे विराट कोहली

खुरी में झूम उठे। विराट कोहली का आक्रामक जश्र देखते बन रहा था। अय्यर मुंबई इंडियंस के खिलाफ कालिकापर-2 के हीरो थे। हर किसी को पता था कि वह क्या कर सकते हैं। जब आउट हुए तो पंजाब के खेमे में सन्नटा पसर गया। इस

तरह से 72 रनों पर दूसरा, जबकि 79 रनों पर तीसरा विकेट गिरा। इसके बाद बल्लेबाज आते रहे और अपना विकेट गंवाकर जाते रहे। हालांकि, शशांक सिंह ने जरूर हाफ सेंचुरी जड़ी, लेकिन टीम जीत से सिर्फ 6 रन दूर रह गई। उसने 7 विकेट पर 184 रन बनाए, जबकि भुवनेश्वर कुमार और कुणाल पंड्या ने 2-2 विकेट झटके।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट पर 190 रन बनाए। एक समय मजबूत स्थिति में होने के बावजूद अंतिम ओवरों में उनकी

पारी लड़खड़ा गई। आखिरी के 19 रन बनाने में टीम ने 4 विकेट गंवाए, जबकि आखिरी ओवर में अर्शदीप ने सिर्फ 3 रन दिए, जबकि 3 विकेट गिरे। विराट कोहली ने 35 गेंदों में 43 रन बनाए। कोहली ने इस मैच में आईपीएल इतिहास में सबसे अधिक चौके लगाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया, शिखर धवन के 768 चौकों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए 769 चौके पूरे किए। खचाखच भरे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पंजाब किंग्स के गेंदबाजों ने शुरुआत से ही विकेट निकालने का सिलसिला बनाए रखा और आरसीबी के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। विराट कोहली आरसीबी के शीर्ष स्कोरर रहे, लेकिन उन्होंने धीमी बल्लेबाजी की। कोहली ने 35 गेंदों में 3 चौकों की मदद से 43 रन बनाए। हालांकि, उनकी पारी अपेक्षाकृत थोड़ी स्लो रह गई। जितेश शर्मा ही एकमात्र बल्लेबाज रहे, जिन्होंने 200 से अधिक के स्ट्राइक रेट से रन बनाए। उन्होंने 10 गेंदों में 24 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 2 छक्के शामिल थे।

मयंक अग्रवाल (18 गेंदों में 24 रन), लियाम लिविंगस्टोन (15 गेंदों में 25 रन), रजत पाटीदार (16 गेंदों में 26 रन) और रोमारियो शेफर्ड (9 गेंदों में 17 रन) ने अच्छी शुरुआत की, लेकिन उसे बड़ी पारी में नहीं बदल सके। अर्शदीप के अलावा काइल जैमीसन ने भी 3 विकेट झटके। अजयतुल्ला ओमरजई, विजयकुमार वैशाक और युजवेंद्र चहल ने भी एक-एक विकेट अपने नाम किया।

प्रथम पृष्ठ का शेष...

जमानत नहीं दी तो...

उन्होंने याचिका में कहा है कि इस महिला सुधार गृह में न सही से साफ-सफाई होती है, न ही यहां पीने का साफ पानी दिया जाता है। शर्मिष्ठा ने यह भी बताया कि उन्हें बीमारियां भी हैं और इस महिला सुधार गृह में उन्हें इलाज या दवा की कोई भी सुविधा नहीं मिल रही है। शर्मिष्ठा ने सुरक्षा दिए जाने की मांग की है। लेकिन विडंबना है कि इस जरूरी मुद्दे पर सुनवाई के लिए अलीपुर कोर्ट को फुर्सत नहीं है। बेशर्म पश्चिम बंगाल सरकार ने शर्मिष्ठा को राहत देने की मांग का पुरजोर विरोध किया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने यह भी प्रयास किया था कि शर्मिष्ठा की जमानत अर्जी पर सुनवाई कलकत्ता हाईकोर्ट में गर्मी की छुट्टियों के बाद हो, ताकि उसे पूरे गर्मी की छुट्टी के दरम्यान जेल में ही रहना पड़े। कलकत्ता हाईकोर्ट में अब गुरुवार 5 जून को सुनवाई होनी है।
उधर, मां कामाख्या पर गंदी टिप्पणी करने वाले वजाहत खान को जैसे ही असम पुलिस ने मांगा, वैसे ही उसे बचाने के लिए बंगाल पुलिस ने भी उस पर एफआईआर कर दिया, ताकि असम पुलिस वजाहत को बंगाल से न ले जा सके। वजाहत फरार है, लेकिन बंगाल की अदालतें निश्चित हैं। मां कामाख्या पर गंदी टिप्पणी करने वाले वजाहत खान को लेकर असम पुलिस जैसे ही सतर्क हुई, कलकत्ता पुलिस ने उसके खिलाफ गार्डन रीच थाने में 2 जून को झटपट एफआईआर दर्ज कर दी।
उसी इस्लामी कट्टरपंथी वजाहत खान ने इस्लाम के कथित अपमान पर शर्मिष्ठा पर एफआईआर कराई थी। वजाहत के पाकिस्तान से सीधे लिंक पकड़े गए हैं। लेकिन मुस्लिम तृष्णकरण में अंधी हो चुकी ममता सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं। यह सामने आ चुका है कि वजाहत ने मां कामाख्या, भगवान कृष्ण समेत तमाम हिंदू देवी-देवताओं पर लगातार अपमानजनक टिप्पणियां कर रहा था।
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने कहा, वजाहत खान के खिलाफ मां कामाख्या पर अपमानजनक टिप्पणियां करने के मामले में एक केस दर्ज किया गया है। अब असम पुलिस पश्चिम बंगाल जाएगी और आगे की कार्रवाई करेगी। हम पश्चिम बंगाल पुलिस से इस मामले में सहयोग

मांगेंगे ताकि आरोपी को असम में कार्रवाई के लिए लाया जा सके।

युद्ध-विराम में...

सांसदों से मुलाकात की। इस दौरान वहां के नेताओं ने ब्राजील को भारत का सदाबहार मित्र करार दिया। तेजस्वी सूर्या ने ब्राजील की यात्रा को सफल बताया। वहां के नेताओं ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से बातचीत के दौरान कहा कि उनका देश हमारा हर मौसम में सहयोगी और हर मौसम का दोस्त है। सूर्या ने यह भी कहा कि ब्राजील के अलावा गुयाना, पनामा और कोलंबिया से भी हमें पूरा समर्थन हासिल हुआ है। यह उपलब्धि भारतीय प्रतिनिधिमंडल के लिए बहुत अहम है। खास तौर पर लैटिन अमेरिका में और सामान्य रूप से पूरे विश्व में ब्राजील एक जरूरी और महत्वपूर्ण आवाज है। वहां गए भारतीय प्रतिनिधिमंडल में शशि थरूर, सरफराज अहमद, गंटी हरीश मधुर, शशांक मणि त्रिपाठी, भुवनेश्वर कलिता, तेजस्वी सूर्या और पूर्व राजदूत तरनजीत सिंह संधू शामिल हैं।

अब तक शरणार्थी ...

चरागाह और तालाब पर भी बसे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन्हें अन्यत्र जमीन देने या फिर उसी जमीन पर स्वामित्व अधिकार देने के लिए कानून में बदलाव करने पर विचार करना होगा। उत्तर प्रदेश में बसे पाकिस्तानी शरणार्थियों को अब जमीन का मालिकाना हक मिलने की दिशा में इसे एक अहम कदम बताया जा रहा है। मुरादाबाद के मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने इस संबंध में पूरी जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपी है। रिपोर्ट में उत्तराखंड मॉडल की तर्ज पर शरणार्थियों को संक्रमणीय भूमिधर अधिकार देने की सिफारिश की गई है।

दुनिया शिव की...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बेस्ट लीडर। एरोल मस्क ने भारत को वैश्विक नेता बताया और कहा कि यह चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत इसके बावजूद विनम्र है। एरोल मस्क ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी बात की और भारत का समर्थन किया। उन्होंने कहा,

पाकिस्तान भारत के लोगों का जीवन कठिन नहीं बना सकता। अगर पाकिस्तानी परेशानियां पैदा कर रहा है, तो इस पर एक्शन लिया जाना चाहिए।

परमाणु ब्लैकमेल ...

गुवाहाटी जैसे असम के मैदानों में प्रवाह मानसून के समय 15,000-20,000 घन मीटर/सेकंड है। ब्रह्मपुत्र भारत में प्रवेश के बाद सशक्त होती है। यह एक भारतीय, वर्षा-पोषित नदी प्रणाली है, न कि किसी एक स्रोत पर निर्भर है। पाकिस्तान के लिए वह सच्चाई जो उसे जाननी चाहिए, अगर चीन कभी ब्रह्मपुत्र के जल को कम भी कर दे (जो कि अब तक किसी भी मंच पर न कहा गया है, न संकेत दिया गया है), तो वह भारत के लिए मददगार हो सकता है, क्योंकि हर वर्ष असम में आने वाली भीषण बाढ़ लाखों को विस्थापित करती है और भारी तबाही लाती है। पाकिस्तान, जिसने 74 वर्षों तक सिंधु जल संधि से असमान लाभ उठाया, अब घबरा रहा है क्योंकि, भारत अपने जल अधिकारों पर संप्रभु निर्णय ले रहा है।
इस संबंध में पाकिस्तान को कुछ याद दिलाना जरूरी है जैसे, ब्रह्मपुत्र एक ही स्रोत पर आधारित नहीं है। यह हमारे भूगोल, हमारे मानसून और हमारी सभ्यतागत शक्ति से पोषित है। मुख्यमंत्री सरमा ने तथ्यों के आधार पर पाकिस्तान की डर वाली रणनीति की जहां हवा निकाल दी, वहीं चीन को भी एक तरह से उत्तर दिया है कि, ब्रह्मपुत्र को लेकर वह भारत को ब्लैकमेल नहीं कर सकता है।
ब्रह्मपुत्र नदी चीन से भले ही आती हो, लेकिन इसका ज्यादातर पानी भारत में ही बनता है। चीन ब्रह्मपुत्र के कुल पानी में सिर्फ 30-35 प्रतिशत का योगदान देता है, और वह भी ज्यादातर पिघलते ग्लेशियरों से आता है। बाकी 65-70 प्रतिशत पानी तो भारत के भीतर ही बनता है, खासकर अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और मेघालय में होने वाली भारी मानसूनी बारिश से। सिंधु जल समझौता स्थगित होने के बाद पाकिस्तान भारत के खिलाफ अलग-अलग पैंतरे चल रहा है।
उसने हाल ही में ब्रह्मपुत्र नदी पर प्रलाप चालू किया है। इस बार उसने यह डर फैलाने की कोशिश की है कि अगर चीन ब्रह्मपुत्र का पानी रोक दे तो क्या होगा? उसके इस प्रोपेगेंडा का

जवाब असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने दिया है।

मुख्यमंत्री हिमंत ने साफ किया कि ब्रह्मपुत्र नदी चीन से भले ही आती हो, लेकिन इसका ज्यादातर पानी भारत में ही बनता है। चीन ब्रह्मपुत्र के कुल पानी में सिर्फ 30-35 प्रतिशत का योगदान देता है, और वह भी ज्यादातर पिघलते ग्लेशियरों से आता है। उन्होंने बताया कि बाकी 65-70 प्रतिशत पानी तो भारत के भीतर ही बनता है, खासकर अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और मेघालय में होने वाली भारी मानसूनी बारिश से। इसके अलावा, सुबनसिरी, लोहित, कामेंग, मानस, धनसिरी, जिबा-भरली, कोपिली जैसी कई बड़ी सहायक नदियां भी हैं जो ब्रह्मपुत्र में पानी डालती हैं। सीएम हिमंत बिस्व सरमा ने कहा कि मेघालय की खासी, गारो और जयंतिया पहाड़ियों से भी कृष्णाई, दिगारू, कुलसी जैसी नदियों के जरिए ब्रह्मपुत्र में खूब पानी आता है और भारत-चीन सीमा पर (तूँगिंग में) ब्रह्मपुत्र का प्रवाह लगभग 2,000-3,000 घन मीटर/सेकंड होता है। उन्होंने कहा कि असम के मैदानी इलाकों में (जैसे गुवाहाटी में), मानसून के दौरान यह प्रवाह बढ़कर 15,000-20,000 घन मीटर/सेकंड हो जाता है। इसका मतलब है कि ब्रह्मपुत्र भारत में आने के बाद और भी बड़ी और शक्तिशाली हो जाती है। यह एक भारतीय, बारिश से पोषित नदी प्रणाली है, जो किसी एक स्रोत पर निर्भर नहीं है।

कुरख्यात बाटला...

में न तो पार्टी बनाया और न ही अपना पक्ष रखने का मौका दिया। बाटला हाउस में अवैध तरीके से कब्जा करके पिछले कई सालों से रह रहे लोगों को दिल्ली विकास प्राधिकरण ने एक नोटिस भेजा था।
इसमें प्राधिकरण ने कब्जाधारियों को 27 मई 2025 को 15 दिन का समय दिया और कहा कि तय समय के अंदर वे अतिक्रमण हटा लें, उसके बाद प्रशासन अवैध निर्माण को ध्वस्त करेगा। फिर क्या था बाटला हाउस की मालकिन सुलताना शाहीन समेत 39 अन्य लोगों ने वकील आदिल अहमद के जरिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। 2 जून को इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फौरी राहत देने से इंकार कर दिया।

उपाय : आज सुबह स्नान ध्यान के बाद
मां दुर्गा के मंदिर में जाकर घी का दीया
जलाएं और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें।
इसके साथ ही मां को लाल चुनरी और
शृंगार पिटाई चढ़ाएं। इससे आपके
मनोरथ पूरे होंगे।

तुषार कपूर की एकलौती फिल्म **मुझे कुछ कहना है** मचाई धूम

7 करोड़ में बनी और कई गुना ज्यादा हुई कमाई

बॉ लीवुड एक्टर तुषार कपूर का एक्टिंग करियर बतौर कॉमेडियन तो सफल रहा, लेकिन उन्होंने जब भी बतौर लीड एक्टर काम किया तो वो फिल्म नहीं चली। लेकिन ऐसा नहीं है कि तुषार के करियर में एक भी सोलो हिट फिल्म नहीं आई। तुषार कपूर की एकलौती सुपरहिट फिल्म जिसमें वो लीड एक्टर थे और उस फिल्म ने कमाई भी जबरदस्त की थी, उस फिल्म का नाम है 'मुझे कुछ कहना है'।

तुषार कपूर और करीना कपूर की इस सुपरहिट फिल्म के गाने भी हिट हुए थे और इसकी कहानी भी लोगों को पसंद आई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर गजब की कमाई की थी और ये तुषार की एकलौती सोलो सुपरहिट फिल्म बन गई थी।

**‘मुझे कुछ कहना है’ का बॉक्स
ऑफिस कलेक्शन**

25 मई 2001 को रिलीज हुई फिल्म मुझे कुछ कहना है का निर्देशन सतीश कौशिक ने किया था जबकि इसके प्रोड्यूसर वाशु भगनानी थे। फिल्म में एक प्यारी सी लव स्टोरी दिखाई गई जिसे सतीश कौशिक ने ही लिखा था। फिल्म में तुषार कपूर और करीना कपूर लीड रोल में थे, वहीं अमरीश पुरी, रंकी खन्ना, दिलिप ताहिल, नथानी शिवापुरी, हेमंत पांडे, आलोक हिमान्न जैसे कलाकारों ने भी अहम किरदार निभाए थे।

फिल्म मुझे कुछ कहना है (2001)
अब अगर कमाई की बात करें तो इस
फिल्म ने वर्ल्डवाइड 29।95 करोड़ का
क्लेक्शन किया था, जबकि इसका बजट



महज 7 करोड़ रुपये था। फिल्म का वर्डिक्ट सुपरहिट था और ये तुषार कपूर की ऐसी सुपरहिट फिल्म थी, जिसमें वो हीरो थे।

यह भी पढ़ें- दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे लें? यहां जानें स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस

फिल्म मुझे कुछ कहना है में लगभग 10 गाने थे, जिनमें से 'आ रंग दे दुपट्टा मेरा', 'जब से देखा है तेरे हाथ का चांद', 'मैंने कोई जादू नहीं किया', 'मुझे कुछ कहना है', 'रब्बा मेरे रब्बा मेरे' और 'रहना है तेरे

दिल में' जैसे गाने सुपरहिट थे। फिल्म में दिखाया गया है कि करण (तुषार कपूर) नाम का एक लड़का पूजा (करीना कपूर) से प्यार करता है, लेकिन बोल नहीं पाता।

पूरी फिल्म में उसके घरवाले और दोस्त उससे कहते रहते हैं कि वो बोल दे, लेकिन उसकी

नहीं होती, लेकिन वो उससे प्यार बहुत करता है। पूजा भी उससे प्यार करने लगती है, लेकिन वो चाहती है कि करण ही उससे कहे। अब करण अपने प्यार का इजहार कब करता है, कब नहीं ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी चाहिए। इस फिल्म को ओटीटी पर देखने के लिए आपको अमेज़न प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। वैसे ये फिल्म यूट्यूब पर भी आपको फ्री में देखने को मिल सकती है।



आश्रम 3 की सफलता के बाद दर्शन कुमार ने बिहार में शुरू की सस्पेंस थ्रिलर की शूटिंग



वे ब सीरीज आश्रम 3 की शानदार सफलता और द फैमिली मैन के अगले सीज़न की रिलीज़ का इंतज़ार कर रहे अभिनेता दर्शन कुमार अब अपने नए प्रोजेक्ट में पूरी तरह से व्यस्त हो गए हैं। उन्होंने अपने अगले अनाइटडब्ल्यू सर्वेस थ्रिलर की शूटिंग शुरू कर दी है, जो फिलहाल बिहार में चल रही है। हमेशा से ही अलग

और दिलचस्प स्क्रिप्ट चुनने के लिए जाने जाने वाले दर्शन कुमार ने यह खास खबर सीधे अपने शूटिंग सेट से साझा की। उन्होंने कहा, बहुत उत्साहित हूँ यह खबर आप सब के साथ शेयर करने के लिए! एक सस्पेंस थ्रिलर के साथ कल से एक नया सफर शुरू हो रहा है, जो सचमुच एन-ऑफ-द-सीट होने वाला है। 'एनएच 10' और 'धोखा - राउंड डी कॉर्नर' के बाद, मैं एक ऐसी कहानी का इंतजार कर रहा था, जो सच में दिल को छू जाए, और यह वही कहानी है। अपने किरदार के बारे में बात करते हुए, दर्शन ने कहा, सबसे ज्यादा उत्साहित मैं इस बात को लेकर हूँ कि मेरा किरदार इस बार काफी चैलेंजिंग है, लेयर्ड है, इंसैस है, और कुछ ऐसा है, जो मैंने पहले कभी नहीं किया। उन्होंने आगे कहा, यह किरदार मुझे एक एक्टर के रूप में पुनः करेगा, और मैं इस किरदार को स्क्रीन पर लाने के लिए काफी उत्साहित हूँ।

इस फिल्म का निर्देशन राव देवेंद्र कर रहे हैं, और इसके निर्माता सागर श्रीवास्तव हैं। इसके सिनेमैटोग्राफर मशहूर अतार सिंह सैनी हैं, जो इस प्रोजेक्ट को एक विजुअली धमाकेदार थ्रिलर बनाने वाले हैं। बिहार में एक लंबे शेड्यूल के लिए शूटिंग की योजना बनाई गई है, और दर्शन इस नए प्रोजेक्ट में पूरी तरह से उतर गए हैं।

दर्शन ने एक भावनात्मक नोट के साथ अपनी बात खत्म करते हुए कहा, यह प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत स्पेशल है, और मुझे पता यकीन है कि आप सब सरप्राइज़ होने वाले हैं। ज़रूरी मिला है और अपडेट्स शेयर करता रहूँगा। आप सबका प्यार और आशीर्वाद बना रहे। यह फिल्म दर्शन कुमार के करियर की एक और उपलब्धि है, जहाँ वे नए एक्सपेरिमेंट्स के साथ-साथ अपने एक्टिंग ग्राफ को और ऊपर ले जा रहे हैं, और दर्शकों के लिए कुछ नया तथा कुछ अलग लेकर आ रहे हैं।

गुजराती सिनेमा को नई पहचान देने
में मेरा महत्वपूर्ण योगदान : मानसी



राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री मानसी पारेख अपनी वाली गुजराती डार्क कॉमेडी थ्रिलर शुभचिंतक को लेकर चर्चा में हैं। वह इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने गीजनल सिनेमा के बदलते स्वरूप के बारे में बात की। उनका मानना है कि उन्होंने ऐसी फिल्मों में काम किया है जो महिलाओं की मजबूत भूमिकाएं दिखाती हैं और इस तरह उन्होंने गुजराती सिनेमा का स्तर ऊंचा उठाने में योगदान दिया है। अपनी नई फिल्म शुभचिंतक में अपने किरदार को लेकर बात करते हुए मानसी ने कहा कि उन्होंने अब तक कई तरह के अलग-अलग किरदार निभाए हैं। मानसी ने कहा, कच्छ एक्स्प्रेस में मैंने एक बहुत सीरी-सादी और शांत स्वभाव वाली पत्नी का किरदार निभाया था। झमकुड़ी में मैं चुड़ैल बनी थी जो गांव में डर फैलाती है। डियर फादर में मैंने एक जिद्दी बहू का किरदार निभाया था, जो अपने ससुर की बातों को नहीं मानती। लेकिन शुभचिंतक में मेरा किरदार पहले से बिल्कुल अलग है। इसमें मैं एक ऐसी लड़की बनी हूँ जो अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए एक अमीर लड़के को प्यार के जाल में फंसाती है। मैंने अपने तक जितने भी किरदार निभाए हैं, वे सब एक-दूसरे से अलग थे, लेकिन ऐसा किरदार मैंने पहले कभी नहीं किया। उन्होंने बताया कि इस फिल्म में उन्होंने कई ऐसे एक्शन सीन किए हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं किए थे। एक्स्ट्रे से कहा, यह किरदार मेरे लिए एक कलाकार के तौर पर नई चुनौती थी। मेघना का किरदार निभाना मेरे लिए बहुत खास और शानदार अनुभव रहा, और मैं इस मौके के लिए बहुत आभारी हूँ। गीजनल सिनेमा के बदलाव को लेकर मानसी ने कहा, अब ज्यादा से ज्यादा लोग क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों देख रहे हैं। गुजराती सिनेमा में भी कई ऐसे फिल्में बन रही हैं। मुझे लगता है कि मेरा योगदान ये रहा है कि मैंने ऐसी फिल्में चुनीं जिनमें महिलाएं मुख्य और मजबूत किरदार निभाए। मैंने कोशिश की है कि औरतों को केंद्र में रखकर अच्छी कहानियां बनाई जाएं। उन्होंने आगे कहा कि पहले फिल्मों में महिलाओं को ज्यादा अच्छी भूमिकाएं नहीं मिलती थीं। आज भी कुछ दिक्कतें हैं, लेकिन वह चाहती है कि औरतों को मजबूत और अहम किरदार मिलें, इसलिए वह ऐसी फिल्में चुनती हैं जिनमें महिलाओं का किरदार सबसे ज्यादा मायने रखता हो।

कृष्णा शॉफ ने खबी सिरनेड कॉर्सेट ड्रेस में बिखेरा जादू



कृष्णा श्राफ ने हाल ही में एक पुरस्कार समारोह में अपनी शानदार उपस्थिति से सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उन्होंने एक 'रूबी सिरेनेड कॉन्सर्ट ड्रेस' पहनी थी, जो ग्लैमर और एलिगेंस का बेहतरीन संगम थी। इस ड्रेस का स्ट्रक्चर्ड सिलहूट न केवल स्टाइलिश था, बल्कि बेहद आरामदायक भी था, जिससे कृष्णा की पूरे मौजूदगी के दौरान बेहद आकर्षक और प्रभावशाली लगीं। उन्होंने अपने लुक को एक स्लीक हाई ब्रेड (ऊँची गुंथी चोटी) के साथ सिंपल लेकिन एलिगेंट रखा। उनके हीरे और रूबी जड़े हुए झुमके और हार ने पूरे लुक में नफासत और चमक का सही स्पर्श जोड़ा।

उनके पहनावे का गहरा, उप लाल रंग

उनके आत्मविश्वास और सहजता को बाखूबी उभार रहा था। मेकअप की बात करें तो, कृष्णा ने नम और ग्लोइंग स्किन के साथ सॉफ्ट ग्लैम लुक अपनाया, जिसमें आंखों पर खास फोकस था। विंड आउटलाइनर और हल्के शिम्परे ने उनके आउटफिट के लाल रंग को और भी ज्यादा निखार दिया।

कुल मिलाकर कहा जाए तो, कृष्णा ने सिर से पाँव तक यह लुक पूरी तरह से कैरी किया। यह हिफ फेशन स्टेटमेंट नहीं था, बल्कि यह दर्शाता है कि सोच-समझकर चुना गया ग्लैमर भी बेहद प्रभावशाली हो सकता है। इस लुक के साथ, कृष्णा श्रॉफ ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वे आधुनिक और सजग फैशन की नई मिसाल बन चुकी हैं।

कावेरी कपूर की 'डबलिन डायरीज़' ने फैंस को आयरलैंड घूमने के दिखाए ख्वाब

सि गर, साँगराइट और अभिनेत्री कावेरी कपूर की हालिया सोशल मीडिया पोस्ट ने ट्वैल लवर्स को जबरदस्त वॉन्डरलस्ट में डाल दिया है। कावेरी इन दिनों 'डबलिन की शांत और सुमुख्य फ़िल्माओं का आनंद ले रही हैं और उन्होंने अपने 'डबलिन डायरीज़' पोस्ट के ज़ोर पर फ़ैस को जबरदस्त ट्वैल क़चज दे दिया। उन्होंने आयरलैंड की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक जीवंतता की कुछ दिल छू लेने वाली झलकियां साझा कीं। हरी-भरी वादियों पर छाए नाटकीय बादलों से लेकर, पूरी तरह खिले हुए चेरी ब्लॉसम्स, शांत झीलों के किनारे उगते और डूबते सूज़, पहाड़ों का साफ़ पानी में प्रतिबिंब, रंग-बिरंगी झिल्लों, और आइकोनिक पिंक 'लूसीज़ विंटेज लाउंज'-कावेरी की यह पोस्ट मानो हमें वर्चुअल टूर पर ले गई हो।

कावेरी इन दिनों इंडस्ट्री में छाई हुई हैं। हाल ही में उन्होंने कुणाल कोहली की 'बाँबी और ऋषि की लव स्टोरी' से बहुमुखीशित बॉलीवुड डेब्यू किया, जिसे ओटीटी पर खूब सराहा गया। उनकी परफॉर्मेंस को भी आलोचकों और दर्शकों से भरपूर तारीफ मिली। रविवंश के साथ-साथ कावेरी म्यूजिक की दुनिया में भी अपनी छाप छोड़ रही हैं। अब तक वह चार म्यूजिक वीडियोज कर चुकी हैं।

अपनी डेब्यू फिल्म का गाना 'एक धागा तोड़ा मैंने' भी उन्होंने खुद गाया है, जो उनका पाँचवाँ म्यूजिक वीडियो बन गया है। इसके अलावा, कावेरी ने अपने क्रिएटिव सफर में एक और उपलब्धि जोड़ी है। उन्होंने हाल ही में 'एक धागा' का मूल अंग्रेजी वर्जन 'रेमिनिस्' रिलीज किया। यह बेहद निजी ट्रैक अपने लिए खास महत्व रखता है, क्योंकि उन्होंने इसे तब लिखा था, जब वह सिर्फ 15 साल की थीं।

इस गाने में उन्होंने अपनी शुरुआती गीत लेखन क्षमता और भावनात्मक परिपक्वता का प्रदर्शन किया था। इस गाने को इंडस्ट्री से काफी प्रशंसा मिल रही है। कावेरी की अगली फिल्म मसूम 2 है, जिसमें वह सिनेमा के दिग्गज नसीरुद्दीन शाह और शबाना आज़मी के साथ साहसी स्पेस साइड करने के लिए तैयार हैं। इस फिल्म का निर्देशन उनके पिता और नया भूषण पुरस्कार विजेता शेखर कपूर करेंगे।



**ब्राउन कटआउट ड्रेस में
सामंथा ने चढ़ाया
इंटरनेट का पारा**

सा उथ इंडस्ट्री की टॉप एक्स्ट्रेसेस में शुमार सामंथा रथ प्रभु एक बार फिर अपने लेटेस्ट लुक को लेकर चर्चा में आ गई हैं। हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पर वोग ब्यूटी अवार्ड्स 2025 के रेड कार्पेट से अपनी तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों में सामंथा ब्राउन कलर की डीप कटाआउट बॉडीकॉन ड्रेस में बेहद ग्लैमरस और बोल्ड नजर आ रही हैं। सामंथा ने अपने इस शानदार लुक के साथ कैप्शन में लिखा, मैं वोगब्यूटी अवार्ड्स 2025। इस ड्रेस को डिज़ाइन क्रेशा बजाज ने डिज़ाइन किया है। सामंथा का हेयर और मेकअप भी बेहद एलिगेंट और परफेक्ट लग रहा है जिसे अविनि रमिया और लक्ष निधि ने स्टायल किया है। तस्वीरें विक्रंतस्मृतीयां द्वारा क्लिक की गई हैं। सामंथा के इस अवतार पर फैस और सेलेब्स जमकर प्यार लुटा रहे हैं। कमेंट सेक्शन में लोग उनकी तारीफों के पुल बांधते नजर आ रहे हैं। किसी ने उन्हें स्टर्निंग क्वीन कहा तो किसी ने हॉटनेस ओवरलोडेड बताया। कुछ ही घंटों में पोस्ट को 3 लाख से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं। सामंथा का ये बोल्ड और क्लासी लुक साइकल करे है कि वो सिर्फ एक शानदार एक्स्ट्रेस ही नहीं, बल्कि ट्रेंडसेटर भी हैं। हर बार की तरह इस बार भी उनका स्टायल स्टेटमेंट फैशन लवर्स को इन्फायर कर रहा है। वोग ब्यूटी अवार्ड्स 2025 में उनका यह लुक न केवल इंटरनेट पर वायरल हो गया है बल्कि इन्होंने उन्हें एक बार फिफेन फैशन वर्ल्ड की टॉप डीवाज की लिस्ट में शुमार कर दिया है।



कैबिनेट में सीएम नीतीश ने 47 प्रस्तावों पर लगाई मुहर, कई विभाग में नए पदों के सृजन की मंजूरी

पटना (एजेंसियां)।

सीएम नीतीश कुमार ने कुल 47 प्रस्तावों को स्वीकृति दी। आगामी चुनाव से पहले नौकरी को लेकर किए गए अपने वादे को सीएम नीतीश कुमार हर हाल में पूरा करना चाहते हैं। इसी को देखते हुए उन्होंने कई विभागों में नए पदों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

इनमें सबसे अधिक पद सृजन के प्रस्ताव शिक्षा विभाग से हैं। इसके अलावा अन्य कई विभाग में भी नए पदों के सृजन के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदर्शन की गई है। आइए जानते हैं सीएम नीतीश कुमार ने और किन-किन प्रस्तावों पर स्वीकृति दी।

शिक्षा विभाग में सीएम नीतीश कुमार ने 935 पदों के सृजन के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। इनमें बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड में विभिन्न कोटि के कुल 818 पदों तथा बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के लिए कुल 63 पदों



के सृजन की स्वीकृति दी गई। वहीं शिक्षा विभाग अन्तर्गत संचालित सरकारी विद्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों एवं कार्यालयों की भूमि का सत्यापन, भूमि के विवरण का संकलन एवं संरक्षण तथा विभाग के अन्य विकासात्मक गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए ससमय भूमि की उपलब्धता हेतु संविदा के आधार पर तीन वर्षों के लिए भू-सम्पदा पदाधिकारी के दो एवं सहायक भू-सम्पदा पदाधिकारी के 38 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।

सीएम नीतीश कुमार ने कृषि विभाग के अन्तर्गत बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि-9 (सांख्यिकी) (भर्ती, प्रोन्नति एवं

सेवा शर्त) नियमावली, 2025 के गठन की स्वीकृति दी गई। बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड, पटना में प्रतिनियुक्ति संविदा के आधार पर कुल 653 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।

वहीं समाज कल्याण विभाग के अधीन महिला एवं बाल विकास निगम अंतर्गत मुख्यालय (निगम) जिला, अनुमंडल स्तर पर कुल 390 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। वहीं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में पांच नए प्रशाखाओं का सृजन हेतु बिहार सचिवालय सेवा के अवर सचिव के एक पद, प्रशाखा पदाधिकारी के पांच पद एवं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के 22 पद समेत कुल

28 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अन्तर्गत राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना के लिए चालक का दो पद के सृजन की स्वीकृति दी गई।

नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत बिहार शहरी आयोजन तथा विकास नियमावली, 2014 के प्रावधानों के आलोक में 07 आयोजन क्षेत्र प्राधिकार (बोधगया, गया, राज-गीर, बिहारशरीफ), आरा, मुजफ्फरपुर एवं सहरसा) में पूर्व से सृजित विभिन्न कोटि के 147 पदों को प्रत्यर्पित करते हुए राज्य के प्रत्येक जिला में एक जिला आयोजना क्षेत्र प्राधिकार का कार्यालय गठन करने एवं उक्त 38 कार्यालयों को सौंपे गये कार्य एवं दायित्वों के समुचित निर्वहन के लिए एक सौ बारह करोड़ पांच लाख चौरहत्तर हजार आठ सौ चौवालीस रुपये के अनुमानित वार्षिक लागत व्यय पर विभिन्न

प्रकार के कुल 1350 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।

स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत जितेन्द्र कुमार, औषधि निरीक्षक, पटना-05 सम्प्रति निर्लंबित के विरुद्ध आय से अधिक चल एवं अचल सम्पत्ति के प्रत्यानुपातिक धर्नाशन, सरकारी पद पर कार्यरत अवधि में पद का भ्रष्ट उपयोग तथा निलंबन अवधि के लिए निर्धारित मुख्यालय में बिना यो-गदान किये ही अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप / आरोपों के लिए उन्हें सरकारी सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के ही तहत जटाशंकर पाण्डेय, (बिहार अल्पसंख्यक कल्याण सेवा वरीयता क्रमांक 156/2013) तत्कालीन जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, सिवान सम्प्रति जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, जमुई को सेवा से बर्खास्तगी की स्वीकृति दी गई।

मध्य प्रदेश के दो पत्रकारों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट तत्काल सुनवाई को सहमत

नई दिल्ली (एजेंसियां)।

उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में कथित तौर पर दो पत्रकारों के साथ मारपीट करने के खिलाफ दायर उनकी याचिका पर शीघ्र सुनवाई के लिए सोमवार को सहमति व्यक्त की।

न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की अंशकालीन कार्य दिवस पीठ ने याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता की दलीलें सुनने के बाद मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई।

याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि अवैध रेत खनन गतिविधियों से संबंधित (रेत माफिया के बारे में) रिपोर्टिंग करने पर मध्य प्रदेश के कुछ पुलिस अधिकारियों ने उन पर हमला किया था।

पीठ ने हालांकि सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त करने से पहले याचिकाकर्ताओं से सवाल किया कि उन्होंने राहत के लिए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया?



न्यायमूर्ति शर्मा ने सुनवाई के दौरान पूछा, क्या हमें देशभर के अग्रिम जमानत के मामलों पर केवल इसलिए विचार करना चाहिए क्योंकि इसमें एक पत्रकार शामिल है?

पत्रकारों का पक्ष रखने वाले वकील ने अदालत के समक्ष कहा कि दोनों को अपने जान पर खतरा मंडरा रहा है। उन पर 'झूठे और मनगढ़ंत' मामलों में गिरफ्तारी का खतरा है। उन्होंने कहा, यह बहुत गंभीर मामला है...उन्हें एक पुलिस कार्यालय में पीटा गया...वे अब शरण लेने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं।

याचिका के अनुसार, मारपीट

की यह घटना मई में भिंड जिले में हुई थी, जहां दो पत्रकारों को पुलिस अधीक्षक के कार्यालय के अंदर कथित रूप से पीटा गया था।

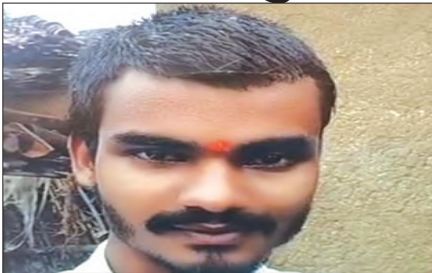
पीठ की ओर से यह पूछे जाने पर कि इस मामले में उच्च न्यायालय क्यों नहीं गए, वकील ने कहा, यह वास्तव में उन मामलों में से एक है...उनके पास साधन नहीं हैं। वकील ने अदालत को यह भी बताया कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने कथित हमले की निंदा की है। उन्होंने संबंधित पत्रकारों के जान पर गंभीरता को जोरदार तरीके से उठाया है।

बिजली विभाग की लापरवाही करंट से 22 वर्षीय युवक की मौत

पटना (एजेंसियां)।

रोहतास जिले के चुटिया थाना क्षेत्र के परछा गांव में मंगलवार की सुबह एक दर्दनाक हादसे में 22 वर्षीय युवक की मौत हो गई। युवक की पहचान मुकेश कुमार मेहता के रूप में हुई है, जो अपने माता-पिता की इकलौती संतान था। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है और परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है।

स्थानीय सूत्रों के अनुसार, मृतक के घर के ऊपर से हाई वोल्टेज विद्युत तार गुजर रहा था, तभी उसने एक लोहे का पाइप उठाया जो ऊपर से गुजर रहे हाई वोल्टेज तार से छू गया। करंट लगने से वह बुरी तरह झुलस गया। परिजन आनन-फानन में उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां



महतो की भी बीते 5 मई को इसी प्रकार करंट लगने से मौत हो गई थी, बावजूद इसके विभाग ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया।

घटना की जानकारी मिलते ही चुटिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल सासाराम भेज दिया। परिजनों के लिखित आवेदन पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद गांव में शोक और आक्रोश का माहौल है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि मृतक के परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए और जिम्मेदार बिजली विभाग के अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं दोबारा न हों।

चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

परिजनों का आरोप है कि बिजली विभाग की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ। उन्होंने बताया कि हाई वोल्टेज तार को हटाने के लिए पिछले कई महीनों से विभाग को आवेदन दिया जा रहा था। विभागीय अधिकारियों द्वारा स्थल निरीक्षण कर एक सप्ताह के भीतर तार हटाने का आश्वासन भी दिया गया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। परिजनों ने यह भी बताया कि मृतक के फूफा लड्डू

मुजफ्फरपुर दुष्कर्म कांड : पीड़िता की मौत पर सियासत तेज, कांग्रेस-राजद समेत विपक्षी दल सड़कों पर

मुजफ्फरपुर (एजेंसियां)।

मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी थाना क्षेत्र में 26 मई को एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म और फिर गला रेतकर हत्या के मामले में अब सियासत तेज हो गई है। विपक्षी दलों ने इस घटना को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस, राजद, सीपीआई, वीआईपी सहित कई विपक्षी पार्टियों ने सरकार के खिलाफ सड़कों से लेकर सदन तक विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है।

जानकारी के अनुसार, मुजफ्फरपुर जिले में एक सप्ताह के भीतर दो नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं सामने



आई, जिनमें से एक बच्ची की इलाज के अभाव में मौत हो गई। इस दर्दनाक घटना ने राज्यभर में आक्रोश की लहर पैदा कर दी है। राहुल गांधी ने इस घटना पर ट्वीट कर गहरी नाराजगी जताई, जिसके बाद बिहार कांग्रेस सड़कों

पर उतर आई और विरोध प्रदर्शन शुरू किया। इसके बाद राजद भी सक्रिय हो गई और अपने सभी विंग्स के साथ विरोध-प्रदर्शन में शामिल हो गई। छात्र विंग, महिला विंग और जिला स्तरीय कार्यकर्ताओं ने सरकार के

खिलाफ पुतला दहन करते हुए नाराजगी जताई।

नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कुढ़नी पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने इस घटना के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि बिहार में कानून-व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है।

प्लुरल्स पार्टी की प्रमुख पुष्पम प्रिया चौधरी ने भी इस मामले पर सरकार को कठघरे में खड़ा करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह सरकार 'गुंडाराज' को बढ़ावा दे रही है और राज्य की बेटीयां असुरक्षित महसूस कर

रही हैं।

वहीं सोशलस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया ने भी इस कांड के विरोध में मुजफ्फरपुर में मार्च निकाला और सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ जिलाधिकारी सुब्रत सेन को ज़ापन सौंपा। पार्टी ने चेतावनी दी है कि यदि ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई, तो विरोध और उग्र होगा। बिहार में इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दल अब इस मुद्दे को लेकर सरकार को चौतरफा घेरने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। लगातार हो रही दुष्कर्म की घटनाओं पर सरकार की चुप्पी और कार्रवाई की धीमी गति को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है।

दी। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना के संबंध में चिरैया डीएसपी अशोक कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आपसी रंजिश का प्रतीत हो रहा है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एसआईटी टीम का गठन किया गया है। परिजनों के बयान के आधार पर प्रारंभिकी दर्ज की जाएगी और शीघ्र ही मामले का उद्घेदन कर लिया जाएगा।

मसौढ़ी जेल में कैदियों द्वारा शराब और गांजा पीने का वीडियो वायरल, जेल प्रशासन पर उठे सवाल

जहानाबाद (एजेंसियां)।

जहानाबाद जिले से सटे पटना जिले के मसौढ़ी अनुमंडल जेल से एक सनसनीखेज वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ कैदी शराब और गांजा का सेवन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में कैदी न सिर्फ खुलेआम शराब पीते दिख रहे हैं, बल्कि गांजे का भी धुआं उड़ाते नजर आ रहे हैं। इस वायरल वीडियो ने बिहार की जेल व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

गौरतलब है कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू है और न सिर्फ शराब का सेवन, बल्कि इसका भंडारण और बिक्री भी पूरी तरह प्रतिबंधित है। ऐसे में सुरक्षा के घेरे में रहने वाले जेल परिसर पहुंच कैसे रही है? यह एक गंभीर जांच का विषय है।

जैसे ही यह वीडियो सामने आया, पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। हालांकि अभी तक इस वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है कि यह कब और किस तारीख का है। जब इस वीडियो को लेकर उपकारा मसौढ़ी के जेल अधीक्षक और जेलर से प्रतिक्रिया मांगी गई, तो उन्होंने इसे पुराना वीडियो बताकर अपना पल्ला झाड़ लिया और कहा कि



इसका वर्तमान में जेल प्रशासन से कोई संबंध नहीं है।

लेकिन वीडियो में स्पष्ट रूप से कैदियों को कहते हुए सुना जा सकता है कि वे उपकारा मसौढ़ी में बैठकर शराब और गांजा पी रहे हैं, जिससे यह जाहिर होता है कि वीडियो मसौढ़ी उपकारा का ही है। यह सीधे-सीधे जेल नियमों और कानूनों का उल्लंघन है। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि जेल के भीतर इतनी सख्त सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद शराब और गांजा आखिर कैसे पहुंच रहा है? क्या इसमें जेल प्रशासन की मिलीभगत है या सुरक्षा व्यवस्था में कोई बड़ी चूक? इन सवालों का जवाब तलाशना अब जरूरी हो गया है।

इस पूरे मामले को जेल आईजी ने गंभीरता से लेते हुए उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। यदि निष्पक्ष जांच हुई, तो निश्चित रूप से दोषियों की पहचान हो सकेगी और इस बात का खुलासा होगा कि आखिर जेल में नशे की सामग्री किस रास्ते से पहुंची और इसमें कौन-कौन लोग जिम्मेदार हैं।

फिलहाल जेल प्रशासन की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं और आम जनता में भी इस घटना को लेकर आक्रोश है। लोग जानना चाहते हैं कि जब बाहर शराबबंदी कानून का सख्ती से पालन कराया जा रहा है, तो फिर जेल के भीतर यह कानून कैसे ठेंगे पर रखा जा रहा है।